राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 9 जुलाई • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, वैसे ही वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है।
-वेदांग ज्योतिष

पारदर्शिता भी जरूरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपेक्षाकृत शांत अवधि के दौरान भी अनिश्चितता के लिए तैयार रहना चाहिए। शांति के समय को भ्रम बताते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सशस्त्र बलों के पराक्रम की भी उन्होंने सराहना की। सिंह ने रक्षा लेखा विभाग के अपने संबोधन में कहा कि विश्व हमारे रक्षा क्षेत्र को सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। अधिकतर उपकरण जो हम पहले आयात करते थे, अब देश में ही बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों को बाहरी ऑडिट या सलाहकारों पर निर्भर रहने की बजाय आत्मावलोकन द्वारा आंतरिक सुधार करने की सलाह भी दी। बीते साल वैश्विक सैन्य व्यय के तकरीबन पाँच तीन लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर पर

पहुंचने की चर्चा करते हुए रक्षा मंत्री ने इसे स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए अपार अवसर बताया। इस संबोधन में अनिश्चितता व शांति के समय को भ्रम बताने के पीछे की उनकी रणनीति चुनौती के तौर पर समझी जा सकती है। बेशक, मुल्क के आंतरिक व सीमापार से होने वाले हमलों पर गोपनीयता बरतना हितकारी है मगर ऐसे किसी भी संकट के प्रति सरकार को सेना को सतर्क भी रखना होगा। मेक इन इंडिया के लॉन्च के बाद यानी 2014-15 से 2023-24 तक भारत का रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। रक्षा मंत्रालय ने 2024-25 में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 193 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि इनमें से 92% घरेलू रक्षा उद्योग को दिए गए। रक्षा उपकरणों पर आत्मनिर्भरता देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उन महाशक्तियों के लिए भी चुनौती है, जिनका इस क्षेत्र में एकछत्र राज रहा है। रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता के चलते अब 65% रक्षा उपकरण घरेलू स्तर पर निर्मित हो रहे हैं। चूंकि रक्षा मंत्रालय की ऑडिट रिपोर्टों सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं होतीं इसलिए सरकार व सैन्याधिकारियों का जिम्मा है कि अपनी समीक्षा स्वयं करें। हालांकि लंबे समय से रक्षा विभाग की मीडिया नीति को लेकर विवाद रहा है। गोपनीय या संवेदनशील रिपोर्टों के अतिरिक्त अन्य लेखा परीक्षक सूचनाओं के आधार पर नियम बनाए जा सकते हैं ताकि किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ियों से रक्षा विशेषज्ञों, संबंधित विश्लेषकों आदि को प्रचारित/प्रसारित किए बगैर विचार का मौका प्राप्त हो। आंतरिक समीक्षा के बावजूद पारदर्शिता देश और देशवासियों के हित में कम आवश्यक नहीं कही जा सकती।

ट्रंप की तिलमिलाहट

फिलस्तीन और पश्चिम एशिया के लिए कोई न्याय की बात करे यह बात नेतन्याहू और ट्रंप को हजम नहीं होती। यही कारण है कि जब ब्रिक्स देशों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, अस्थिरता और गाजा के खिलाफ इस्राइली हमलों और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की तो ट्रंप तिलमिला उठे। जब ट्रंप अपने देश में यहूदी विरोध के बहाने अपने ही विश्वविद्यालयों पर तमाम पाबंदियां लगा सकते हैं तो ब्रिक्स देशों की यह हरकत कैसे बर्दाश्त करते। फलस्वरूप उन्होंने इन देशों पर ही अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी तक दे डाली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त घोषणापत्र ट्रंप के तिलमिलाने का कारण साबित हुआ। घोषणापत्र में कही गई हर बात ट्रंप और नेतन्याहू का मुंह

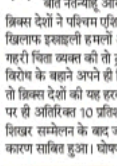

ही नहीं चिढ़ाती, बल्कि इसकी भी झलक दिखाती है कि बदलती दुनिया क्या चाहती है। घोषणापत्र में ब्रिक्स देशों ने दोहराया कि इस्राइल-फिलिस्तीन संघर्ष का न्यायसंगत और स्थायी समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों की पूर्ति पर निर्भर करता है, जिसमें आत्मनिर्णय और वापसी के अधिकार शामिल हैं। ब्रिक्स ने क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन करने का आह्वान किया है, और मानवीय सहायता के राजनीतिकरण और सैन्यीकरण के प्रयासों की निंदा की। घोषणापत्र सामने आते ही ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया जताई और ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली और कहा कि इसका कोई अपवाद नहीं होगा। लगता है कि ट्रंप ने अपवाद न होने वाली बात कह कर भारत को भी अपना रुख कड़ा करने का इशारा दे दिया है। चीन ने राष्ट्रपति ट्रंप की इस धमकी पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीतिक दबाव का निरर्थक साधन बताया। लेकिन ट्रंप भारत के साथ एक बड़े व्यापार समझौते का जो इशारा देते रहे हैं, लगता है वह उलझ सकता है। अभी तक तो भारत इस्राइल विरोधी किसी भी मुहिम में शामिल होने से किनारा करने की नीति पर चलता रहा है, लेकिन लगता है कि ब्रिक्स घोषणापत्र भारत की मजबूरी बन गया है। ब्रिक्स के मूल सदस्यों में शामिल रूस और चीन के तो अमेरिका के दबाव में आने की बात सोचना भी संभव नहीं है, लेकिन भारत, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं।

जीएसटी स्लैब/डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

बदलाव से सुधरेंगे हालात

वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की चार स्लैबों में से दूसरी 12 प्रतिशत की स्लैब को लेकर जिस तरह की चर्चा हो रही है उससे मध्य व निम्न वर्ग की उम्मीदों को पंख लगे हैं। दरअसल, समाज का मध्यम और निम्न वर्ग सबसे अधिक प्रभावित जीएसटी की 12 प्रतिशत वाली स्लैब से ही हो रहे हैं।

इन वर्गों से जुड़ी वस्तुएं या सेवाओं पर लगने वाला कर सीधा सीधा इन्हें प्रभावित करता है। इसका कारण भी साफ है कि दैनिक उपभोग की अधिकांश वस्तुएं इसी स्लैब में आती हैं। खाने-पीने की वस्तुओं के साथ ही जूते-चप्पल, कपड़े आदि भी इसी स्लैब में आते हैं। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार 12 प्रतिशत की स्लैब पर निर्णय से सरकार पर 40 से 50 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का असर पड़ेगा पर यह भी माना जा रहा है कि बाजार में इन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से काफी मात्रा में राजस्व पूर्ति हो सकेगी। हालांकि इस निर्णय के भी बिहार सहित अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव से जोड़कर राजनीतिक अर्थ निकाले जाएंगे पर इस तरह के निर्णयों पर राजनीति करना उचित नहीं कहा जा सकता। जानकारों के अनुसार जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में 12 प्रतिशत वाली स्लैब को या तो विलोपित करने पर विचार किया जा सकता है या फिर इसमें से आम उपभोग की वस्तुओं को पांच प्रतिशत की स्लैब के दायरे में लाया जा सकता है। देश में 12 प्रतिशत की स्लैब इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि दैनिक उपभोग की अधिकांश वस्तुएं इसी कर दायरे में आती हैं। एक हजार रुपये से अधिक के कपड़े जूते से लेकर घी, तेल, मक्खन, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, फल, मेवे सहित खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, 20 लीटर पैक में पीने के पानी की बोतल, कॉटन हैंड बैग जूट का सामान, पत्थर और लकड़ी आदि की मूर्तियां, चश्मा, बच्चों की पेंसिल स्लेट, खेल का सामान इस दायरे में आती है। सीधी सी बात यह है कि यह वस्तुएं ऐशो-आराम की वस्तुएं तो है नहीं और कम से कम मध्यवर्गीय परिवार तो इन्हें खरीदता ही है तो निम्न वर्ग परिवार भी दूसरी कटौती या अपना पेट काटकर इन्हें खरीदता है। ऐसे में 12 प्रतिशत की स्लैब पर विचार निश्चित रूप से सकारात्मक संदेश देता है।

इस कोण से समझिए मसला

भाषा विवाद

नवल किशोर कुमार

हिन्दी भाषा को लेकर फिर से विवाद गरमा गया है। इस बार विवाद भाजपा शासित महाराष्ट्र में सामने आया है। हिन्दी को अनिवार्य बनाने की कोशिशों को झटका लगा है। वहां मराठीभाषियों के विरोध को देखते हुए सरकार को अपने कदम खींचने पड़े हैं। हालिया मराठी-हिन्दी विवाद की शुरुआत नई शिक्षा नीति-2020 के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने को लेकर हुई। राज्य शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव आया कि-कक्षा एक से दसवीं कक्षा तक हिन्दी की पढ़ाई शुरू की जाए ताकि विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा के लिए बेहतर रूप से तैयार किए जा सकें।

महाराष्ट्र में पचास के दशक से ही मराठी पहचान को लेकर राजनीति जारी है। मराठी भाषा का सवाल उस दौर से ही बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। यह केवल शिक्षा नीति से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता से भी इसका नाभि-नाल का संबंध है। हालांकि इसके पहले दक्षिण भारत के राज्यों खासकर तमिलनाडु में केंद्र सरकार की पहल का तीखा विरोध हुआ।

हालांकि यह विवाद कोई नया विवाद नहीं है। आजादी के पहले से यह चला आ रहा है लेकिन मूल सवाल यह है कि अब यह विवाद क्यों गहराता जा रहा है? तो इसका जवाब यह है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्यों को तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर विवाद क्यों है, इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में बांग्ला स्थानीय भाषा है, जिसे वहां राजकीय शासन-प्रशासन में इस्तेमाल में लाया जाता है। बांग्ला के अलावा वहां अंग्रेजी को सरकारी मान्यता प्राप्त है, और शिक्षण संस्थानों में भी। अब केंद्र सरकार का कहना है कि वहां तीसरी भाषा के रूप में हिन्दी भी शामिल की जाए। यही स्थिति उन सभी राज्यों में है, जहां की स्थानीय भाषा को पहले से ही सरकारी मान्यता प्राप्त है। यह सवाल कि हिन्दी का विरोध क्यों किया जा रहा है, तो इसके पीछे एक बड़ा सवाल अस्मिता और संस्कृतियों से जुड़ा है। यदि हम तमिलनाडु की ही बात करें तो वहां द्रविड़ संस्कृति रही है, और तमिल को सबसे प्राचीन भाषा का सम्मान भी प्राप्त है। वहां हिन्दी का विरोध कर रहे लोगों का हमेशा तर्क रहा है कि हिन्दी को शामिल करने से हिन्दी से संबंधित संस्कृतियों का समावेशन होगा जिससे द्रविड़ संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा।

असल में भारत, जो विभिन्न धर्मों और मान्यताओं वाला देश है, में हर प्रांत की अपनी मान्यताएं और संस्कृतियां हैं। सही है कि हिन्दी को उत्तर भारत में सर्वोच्च स्थान हासिल है, और इसका विस्तार मध्य भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में है लेकिन हिन्दी को अभी तक राष्ट्रव्यापी समर्थन नहीं मिल सका है और इसकी वजहें विभिन्न संस्कृतियां व उनसे

जुड़ी अस्मिताएं हैं। हिन्दी के विरोध अब इस स्तर तक पहुंच गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी सफाई देनी पड़ रही है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सफाई दी है कि संघ बहुत पहले से मानता रहा है कि भारत की सभी भाषाएं, राष्ट्रीय भाषाएं हैं। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं है। तमिल, कन्नड़, उड़िया, बांग्ला आदि भाषाओं को भारत सरकार ने भले ही आठवीं अनुसूची में जगह दे दी है, लेकिन अब भी राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रचार-प्रसार की वैसी कवायद सामने नहीं आई है, जिस तरह की हिन्दी को लेकर की जाती रही है। इसके साथ यह भी कहा है कि प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा में ही होनी चाहिए।

असल में महाराष्ट्र में विरोध के पीछे की राजनीति को दरकिनार नहीं किया जा सकता लेकिन इसका दूसरा पक्ष, जिसे नई शिक्षा नीति के संदर्भ में जरूर देखा जाना चाहिए, यह है कि तीन भाषाओं को पढ़ने से छात्रों की ऊर्जा का अपव्यय होगा। इसे ऐसे समझें कि कोई छात्र तमिल और अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए हिन्दी पढ़ना अतिरिक्त बोझ के समान होगा। इससे उनकी मेधा प्रभावित होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने जिस नीयत से हिन्दी को पूरे भारत में थोपने की जो कोशिश की है, उसके मूल में हिन्दुत्व का प्रसार है। इसके पहले एक कोशिश संस्कृत के लिए भी की गई और अब भी कई प्रांतों में स्कूली छात्रों के लिए संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। इसके बावजूद कि इस भाषा को पढ़ने का कोई लाभ व्यावहारिक जीवन में नहीं मिलता। यही स्थिति हिन्दी के मामले में भी है। इसकी वजह है हिन्दी की सर्वत्र स्वीकार्यता। मतलब यह कि अंग्रेजी के जरिए आज वैश्विक स्तर पर संवादों का आदान-प्रदान संभव है। बड़ी से बड़ी नौकरियां अंग्रेजी के कारण हासिल की जा सकती हैं। हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन से यह संभव नहीं है।

भाषा के विवाद के मूल में जहां एक ओर हिन्दुत्व को थोपने की संघी मानसिकता तो है ही, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को अंग्रेजी से दूर रख कर उन्हें शासन-प्रशासन से अलग रखने की मंशा भी सामने आती है। वजह यह कि सरकार की नीति कहती है कि हिन्दी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य की जाए। जाहिर तौर पर गैर-हिन्दी छात्र हिन्दी पढ़ने को बाध्य किए जाएंगे तथा अंग्रेजी से दूर किए जाएंगे जबकि देश भर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों मसलन, केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई की भाषा अंग्रेजी है। जब यह व्यवस्था की गई थी तब तर्क था कि इन विद्यालयों में केंद्र सरकार के कर्मियों के बच्चे पढ़ेंगे जिनका स्थानांतरण अलग-अलग राज्यों में किया जाता है लेकिन बाद में यह प्राइवेट स्कूलों में भी आम चलन हो गया।

आज स्थिति यह है कि सुविधा संपन्न लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में अधिक संख्या दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बच्चों की होती है। जाहिर है कि केवल सरकारी स्कूलों में हिन्दी को बढ़ावा और अंग्रेजी को कम महत्व दिया गया तो इसका नुकसान सबसे अधिक इन वर्गों के छात्रों को होगा। और यह बड़ा नुकसान होगा। इससे भारत के विकास की गति धीमी होगी। समाज का यह वर्ग जो पहले से ही शासक वर्ग रहा है, और अधिक मजबूत होगा। जबकि कमजोर तबके के लोग और कमजोर होते जाएंगे। यह इस तरह से होगा कि अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे ऊंचे पदों की नौकरियों के लिए आसानी से योग्य बनते जाएंगे तथा कॉरपोरेट सेक्टर में भी अपने लिए आसानी से स्थान बना सकेंगे जबकि हिन्दी में पढ़ने वाले आरक्षण के बावजूद 'नॉट फाउंड सूटेबिल' करार देकर बाहर कर दिए जाएंगे।

(लेख में विचार निजी हैं)

> आज स्थिति यह है कि सुविधा संपन्न लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में अधिक संख्या दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बच्चों की होती है। जाहिर है कि केवल सरकारी स्कूलों में हिन्दी को बढ़ावा और अंग्रेजी को कम महत्व दिया गया तो इसका नुकसान सबसे अधिक इन वर्गों के छात्रों को होगा। और यह बड़ा नुकसान होगा। इससे भारत के विकास की गति धीमी होगी। समाज का यह वर्ग जो पहले से ही शासक वर्ग रहा है, और अधिक मजबूत होगा। जबकि कमजोर तबके के लोग और कमजोर होते जाएंगे। यह इस तरह से होगा कि अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे ऊंचे पदों की नौकरियों के लिए आसानी से योग्य बनते जाएंगे तथा कॉरपोरेट सेक्टर में भी अपने लिए आसानी से स्थान बना सकेंगे जबकि हिन्दी में पढ़ने वाले आरक्षण के बावजूद 'नॉट फाउंड सूटेबिल' करार देकर बाहर कर दिए जाएंगे।

लहसुन

हार्ट के लिए 'अमृत'

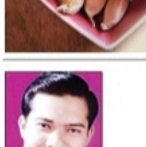

- लहसुन का आयुर्वेद में खास स्थान है। लहसुन का वैज्ञानिक नाम 'एलियम सैटिवम एल' है। लहसुन की उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है। इसकी पैदावार भारत, चीन, फिलीपींस, ब्राजील, मैक्सिको आदि देशों में बड़े स्तर पर की जाती है
- लहसुन की दो-तीन तुरियां रोज चबा लेने से हार्ट फेल की नौबत नहीं आती। इसके सेवन से हृदय पर पड़ने वाला गैस का दबाव कम होता है। यह कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करता है तथा हृदय रोगी को नया जीवन देता है

(मीडिया इनपुट्स)

'सितारे जमीन पर' देखकर लगा कि हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, विशुद्ध रूप से बाजार के लिए बनने वाली फिल्मों में अन्य डिस्क्लेमरों के साथ यह भी लिख देना चाहिए - 'बुद्धिमान दर्शकों के लिए नहीं'। सामाजिकता के खोल में निपट फार्मूला फिल्म है। बोले तो मुंबई वालों का अपना नार्मल!

ओम थानवी, पत्रकार
@omthanvi

मनुष्य | **श्रीराम शर्मा आचार्य**

मनुष्य अपने आपको नहीं पहचान पाता है। वास्तव में जो कुछ वह किया करता है, उसी से कार्यानुसार दंड व यश का भागी बनता है। अब सब कुछ मनुष्य मात्र पर ही रह जाता है। यदि मनुष्य स्वतः को सुधार लेता है तो वह सबको सुधार सकता है परन्तु जब वह स्वतः नहीं सुधरेगा तो दूसरों को कैसे सुधार सकता है। नियमों का विधान पालन करने के लिए ही बनाया जाता है। जब उन विचारों का उल्लंघन किया जाता है, तब मनुष्य अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाता है, तब उसे उस अवस्था में दंड प्राप्त होता है। यही प्रधानता मनुष्य के कर्मों की ही है, वह कर्मानुसार ही फल को प्राप्त होता है। भगवान सबसे प्रेम करते हैं। भगवान की मान्यता ही मानवता का आधार है। चाहे कितनी ही बाधाएं सामने क्यों न खड़ी हों, यदि मनुष्य प्रेमपूर्वक उनका अभिनंदन कर, प्रेम स्वरूप प्रभु का मंगल-विधान समझ अपने पथ पर दृढ़ होकर डटा रहता है तो उसका विकास सदैव सही मार्ग से ही होता है। मनुष्य के लिए कर्त्तव्य की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसके पालन के लिए न तो कोई विशेष प्रयत्न ही आवश्यक हैं, और न कोई साधना की, सीधा पथ है-उस प्रभु का आधार। सब कठिनाइयों का प्रेमपूर्वक स्वागत करें तो आप उन्हें अवश्य जीत सकेंगे। भारी से भारी विपत्ति क्यों न हो, हमें उसका प्रेमपूर्वक अभिनंदन करना चाहिए। भगवान के प्रत्येक विधान में हमारा मंगल भरा है। आज जो विपत्ति व बाधाएं हमारे सामने हैं, उनसे मुंह मोड़ने व भागने की आवश्यकता नहीं है। उनका आविर्भाव तो हमारे कल्याण के लिए ही हुआ है। हो सकता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उपलक्ष के ही वे हमें प्राप्त हो रही हों। हमें कब और किस समय कौन सी वस्तु की आवश्यकता होती है, यह वे अंतर्यामी परम प्रभु स्वतः जानते हैं। परम पिता हमें कितना अपार स्नेह देते हैं, यदि वह रहस्य हम समझ जाएं तो सुख-दुख, शांति-अशांति, दोनों ही हमारे लिए समान हो जाएंगे तथा यश और दंड का भेद ही न रह जाएगा। अपने परम शुभ चिंतक मंगलमय भगवान के प्रत्येक विधान में हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए तथा सबसे प्रेम का व्यवहार कर प्रेम स्वरूप प्रभु को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम ही परमात्मा है, और परमात्मा ही प्रेम है।

रीडर्स मेल

मतदाता सत्यापित होना जरूरी

जिस लोकतंत्र की नींव 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत पर टिकी हो वहां यदि एक मृत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जीवित हो, या एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज हो, तो यह केवल तकनीकी चूक नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। मतदाता सूची में मृत, दोहरे और फर्जी नामों की मौजूदगी केवल गिनती का दोष नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र की वैधता को अंदर से खोखला कर देता है। 2024 तक भारत में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 96.8 करोड़ से अधिक हो चुकी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें से लगभग 3 करोड़ नाम या तो दोहराए गए हैं, फर्जी हैं या अपर्याप्त रूप से सत्यापित हैं। यह स्थिति न केवल निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को संकट में डालती है, बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक छवि पर भी सवाल उठाती है। अब समय है कि मतदाता सूची को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोमेट्रिक जांच और स्थानीय सामाजिक निगरानी के त्रिस्तरीय ढांचे से साफ और प्रमाणित किया जाए।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

हिन्दी का विरोध अनुचित

इन दिनों मुंबई, महाराष्ट्र में मराठी मानुष की मुद्दा काफी जोर पकड़ रहा है, जहां हिन्दी बोलने वालों के साथ बदतमीजी का व्यवहार यहां तक कि मारपीट तक की जा रही है। एक जमाने में जब बाल ठाकरे के समय भी मुंबई में हिन्दी बोलने वालों के साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता था एवं उनसे मराठी बोलने के लिए दबाव डाला जाता था। आजकल एक बार फिर, जब से मनसे एवं उद्धव ठाकरे की शिव सेना के आपस में मिलने की बात की जा रही है, मुंबई में मराठी मानुष की गतिविधियां काफी बढ़ रही हैं। इधर, महाराष्ट्र की भाजपा सरकार का कहना है कि जो भी हिन्दीभाषियों के साथ दुर्व्यवहार करेगा, उसके साथ प्रदेश सरकार सख्ती से निपटेगी। हिन्दी भाषा का इस तरह से अपमान या विरोध करना किसी भी तरह से जायज नहीं है। कुछेक प्रदेशों को छोड़ कर पूरे देश में हिन्दी भाषा को काफी सम्मान दिया जाता है, अतः उसका विरोध करना किसी भी तरह से अनुचित ही कहा जाएगा।

मनमोहन राजावत 'राज', शाजापुर, मप्र

प्रशासन संवेदनशील बने

नदियों का बढ़ता जलस्तर हमें बांधों की सुरक्षा की ओर इशारा कर रहे है। कई जगह देखा गया है कि बांधों के टूटने से जान-माल की बड़ी क्षति होती है। महंगाई बढ़ जाती है, प्रवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है, आवागमन बाधित हो जाता है, लोग अपनों से दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने को खो देते हैं। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कुछ मानवीय प्रयास किए जा सकते हैं ऐसे समय में अपने आप को व्यवस्थित करते हुए समय रहते ऊंचे एवं सुरक्षित स्थान की ओर प्रवास करना चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि समय रहते अपने क्षेत्र के गठबंधन की सुरक्षा सुनिश्चित कर ले एवं लोगों वाहप्रवत क्षेत्र से निकलने के लिए नाव, स्टीमर इत्यादि व्यवस्था करनी चाहिए। ऊंचे स्थान पर रहने के लिए अस्थाई घर, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, राहत सामग्री, चलंत शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था से निश्चित तौर पर लोगों को सुकून मिलेगा।

एस कुमार, वैशाली, बिहार
letter.editorsahara@gmail.com

जीएसटी स्लैब/डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

आईसीयू में मेडिकल सिस्टम

भ्रष्टाचार | **आर.के. जैन**

जब एक देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और उसकी नींव मानी जाने वाली मेडिकल शिक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो यह केवल एक घोटाला नहीं, बल्कि लाखों लोगों के भरोसे और भविष्य पर सीधा हमला है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल में सनसनीखेज खुलासे के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) और निजी मेडिकल कॉलेजों के बीच गहरे भ्रष्टाचार के जाल को उजागर किया है। 34 लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी ऐसी सच्चाई सामने लाई है, जो न केवल मेडिकल शिक्षा की विश्वसनीयता, बल्कि स्वास्थ्य तंत्र के प्रति जनता का विश्वास भी हिलाती है।

यह घोटाला स्वास्थ्य मंत्रालय के गलियारों से शुरू होता है, जहां अधिकारियों ने बिचौलियों और निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ मिल कर ऐसा तंत्र बनाया जो नियमों को तोड़ने-मरोड़ने का पर्याय बन गया। गोपनीय दस्तावेज की चोरी, निरीक्षण कार्यक्रम लीक होना, और मूल्यांकनकर्ताओं की जानकारी कॉलेजों तक पहुंचना-सब सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। इस रेटिंग ने मेडिकल कॉलेजों को वह मौका दिया जिसके जरिए वे निरीक्षण प्रक्रिया को थोड़े में बदल सके। कॉलेजों ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। फर्जी संकाय की नियुक्ति, काल्पनिक मरीजों को भर्ती दिखाना और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में हेरफेर जैसे हथकंडे अपनाए गए। यह सब रिश्वत के खेल का हिस्सा था, जहां लाखों रुपये हवाला के जरिए लेन-देन किए गए। यह धन न केवल व्यक्तिगत लाभ, बल्कि सामाजिक-धार्मिक गतिविधियों के नाम पर भी इस्तेमाल हुआ। खुलासा सवाल उठाता है कि क्या पवित्रता का मुखौटा पहन कर भ्रष्टाचार को छिपाना अब आम बात हो गई है?

मेडिकल शिक्षा का उद्देश्य कुशल और नैतिक डॉक्टर तैयार करना है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करें लेकिन जब यह प्रक्रिया ही भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो तो पढ़ कर निकलने वाले डॉक्टरों की गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजिमी है। यह घोटाला मेडिकल शिक्षा की वैश्विक साख पर गहरा प्रहार करता है। भारत, जो चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है, ऐसे घोटालों के कारण विश्वसनीयता खो रहा है। उन लाखों छात्रों का क्या जो भारी-भरकम फीस चुका कर इन कॉलेजों में पढ़ते हैं? क्या उनकी मेहनत और सपने भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ जाएंगे?

यह घोटाला मेडिकल शिक्षा तक सीमित नहीं है। इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी गंभीर हैं। निजी मेडिकल कॉलेजों का व्यावसायीकरण पहले ही शिक्षा को विलासिता बना चुका है। मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा का सपना और दूर हो जाता है। हवाला के जरिए रिश्वत का लेन-देन अर्थव्यवस्था को खोखला करता है। यह धन, जो जनकल्याण के लिए उपयोग हो सकता था, भ्रष्टाचार के काले गलियारों में गायब हो रहा है। धार्मिक-सामाजिक कार्यों के नाम पर इसका इस्तेमाल न केवल नैतिकता पर सवाल उठाता है, बल्कि समाज के प्रति गहरे विश्वासघात को भी दर्शाता है। यह घोटाला एनएमसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। एनएमसी को भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस घोटाले ने तमाम दावों की पोल खोल दी। स्पष्ट है कि नियामक ढांचे में गहरी खामियां हैं। निरीक्षण प्रक्रिया को डिजिटल और स्वचालित करना, स्वतंत्र ऑडिट अनिवार्य करना, और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना कुछ ऐसे कदम हैं, जो इस तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। यह सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा भी दायित्व है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की दिशा में प्रयास करें।

यह घोटाला एक कड़वी सच्चाई सामने लाता है कि हमारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, लेकिन यह अवसर भी है-सुधार का अवसर, जवाबदेही का अवसर और ऐसी व्यवस्था बनाने का अवसर, जो नैतिकता और पारदर्शिता पर टिकी हो। सीबीआई की कार्रवाई एक शुरुआत है, लेकिन यह तभी सार्थक होगी जब इसके परिणामस्वरूप ठोस बदलाव आएं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि मेडिकल शिक्षा का हर स्तर-प्रवेश से लेकर मान्यता तक-पारदर्शी और जवाबदेह हो। यह न केवल उन छात्रों के लिए जरूरी है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, बल्कि उन करोड़ों मरीजों के लिए भी जरूरी हैं, जिनका जीवन इन डॉक्टरों के हाथों में होता है। यह घोटाला चेतावनी है। बताता है कि हमारी व्यवस्था की कमजोरियों ने हमारे विश्वास से ठगी की है, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। लगातार मेडिकल शिक्षा को भ्रष्टाचार के इस काले साये से मुक्त कराना होगा। बेशक, यह लंबी लड़ाई है, लेकिन अगर हम एकजुट होकर भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ खड़े हों, तो हम एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं, जो न केवल कुशल डॉक्टर तैयार करेगी बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएगी। आइए, इस घोटाले को सबक बनाएं और एक नये, पारदर्शी और नैतिक भारत की नींव रखें।

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

सहारा इण्डिया परिवार कामगिनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कतरी द्वारा सहारा इंडिया पत्रा कामगिनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, कनाकया सार, नकारेर हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश सिन्हा ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23363369, 011-23363372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 321 आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026 *इस अंक में प्रकाशित समाज सरक

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 122

व्यापक अनिश्चितता

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक दर्जन से अधिक देशों को पत्र लिखकर, उनके यहां से अमेरिका को होने वाले आयात पर 25 से 40 फीसदी तक का शुल्क लगाने की बात कही है। यह 1 अगस्त से प्रभावी होगा। जिन देशों को नई शुल्क दरों के बारे में बता दिया गया है उनमें जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं जिनके आयात पर 25 फीसदी शुल्क लगाया जाएगा जबकि कुछ अन्य क्षेत्रवार दरें भी लागू होंगी। इस सूची में भारत का नाम नहीं है और ट्रंप का वक्तव्य संकेत देता है कि भारत और अमेरिका दोनों जल्दी ही एक व्यापार समझौते पर पहुंच सकते हैं। भारत के नजरिये से देखा जाए तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए और सरकार को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि वह अमेरिकी प्रशासन के साथ सक्रियता से बातचीत कर रही है। हालांकि, समझौते की प्रकृति और दोनों पक्षों की ओर से दी जाने वाली संभावित रियायतें अभी तक स्पष्ट नहीं हैं। खबरें बताती हैं कि भारतीय समय के अनुसार मंगलवार देर रात तक समझौते का विस्तृत ब्योरा सामने आ सकता है।

तथाकथित जवाबी शुल्क पर स्थगन की 90 दिन की अवधि समाप्त होने और अमेरिका द्वारा पत्र भेजे जाने के बीच कुछ बातें स्पष्ट हैं। कारोबारी साझेदारों के साथ व्यक्तिगत समझौतों पर बातचीत आसान नहीं है और जैसा कि कई लोगों को डर था, अमेरिका ने एकपक्षीय तरीके से काम करने का निर्णय लिया है। वह अब उन देशों पर भी ऊंची शुल्क दर आरोपित कर रहा है जिनके साथ उसका मुक्त व्यापार समझौता है। सख्त बातचीत के बावजूद अमेरिका केवल यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ ही समझौता कर सका है और वियतनाम के साथ उसके समझौते को लेकर भी कई प्रश्न उठे हैं। चीन के साथ एक समझौता हुआ है लेकिन इसका संबंध दुर्लभ खनिज तत्वों की आपूर्ति से ज्यादा है। इन पत्रों से पता चलता है कि ट्रंप के कदमों के पीछे असल कारण विभिन्न देशों के साथ व्यापार घाटा है। उनके लिए किसी भी देश के साथ व्यापार घाटा, गैरबराबरी का परिचायक है जिसे ठीक किया जाना चाहिए, शुल्क के साथ कम से कम आंशिक रूप से इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

इतना ही नहीं, अगर उसके कारोबारी साझेदार प्रतिरोध करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका शुल्क दर बढ़ाने के लिए भी तैयार है और अगर साझेदार अपने बाजारों को अमेरिकी निवेश के लिए खोलते हैं तो वह शुल्क दरें कम करने का इच्छुक है। अमेरिका के कदम अब यह दिखाते हैं कि बहुपक्षीय वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में नेतृत्व की भूमिका को बचाए रखने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। उसका रुख संकीर्ण सोच वाला और अल्पावधि के आकलन पर आधारित है। इसमें से अधिकांश का ठोस आर्थिक आधार नहीं है। अब जबकि यह स्पष्ट है कि अमेरिकी शुल्क दर ट्रंप की 'लिबरेशन डे' की घोषणा से अधिक होंगे तो यह बात मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों को प्रभावित करेगी और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के आकलन को भी प्रभावित करेगी। इससे मुद्रास्फीति के अनुमानों पर असर पड़ने की संभावना है और यह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की गणना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे मौद्रिक सहजता प्रभावित होगी। ऐसे में ट्रंप फेडरल रिजर्व पर दबाव और बढ़ा सकते हैं। उनका मानना है कि केंद्रीय बैंक नीतिगत ब्याज दरों को स्थिर रखकर सही काम नहीं कर रहा है।

भारत के लिए अभी यह देखना होगा कि अमेरिका के साथ होने वाला नया समझौता घरेलू अर्थव्यवस्था और निर्यात पर क्या असर डालता है। भारत में कृषि क्षेत्र को खोलने को लेकर आशंकाएं हैं क्योंकि वह देश की आधी से अधिक आबादी की आजीविका का साधन है। हालांकि यह देखना अहम होगा कि भारत को अन्य समकक्ष देशों की तुलना में किस प्रकार की टैरिफ रियायत मुहैया कराई जाती है लेकिन संभावित लाभ सीमित ही रहेंगे। अमेरिकी नीति व्यापार घाटे से संचालित है और किसी भी देश के साथ घाटे में इजाफा होने पर दरें बढ़ाई जाएंगी। ट्रंप ने विश्व व्यापार व्यवस्था को अनिश्चित हालात में डाल दिया है और यह देखना होगा कि मध्यम अवधि में हालात क्या मोड़ लेते हैं। काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हालात से कैसे निपटते हैं। भारत को नई विश्व व्यवस्था में उभरते अवसरों के लिए तैयार रहना होगा।

देश का चालू खाते का घाटा और वैश्विक स्थिति

निरंतर बनी हुई वैश्विक अनिश्चितता के बीच चालू खाते का घाटा ज्यादा चिंता का विषय नहीं है लेकिन इसकी भरपाई की बारीकी से निगरानी करनी होगी। बता रहे हैं धर्मकीर्ति जोशी और अधीश वर्मा

गत वित्त वर्ष के दौरान भारत का चालू खाते का घाटा (सीएडी) सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 0.6 फीसदी के स्तर पर रहा जो कि चिंताजनक नहीं है। यह अच्छी विशुद्ध अदृश्य प्राप्तियों की बदौलत हुआ। यह 2023-24 के 0.7 फीसदी से कम था जबकि वस्तु व्यापार घाटा जीडीपी के 6.7 फीसदी से बढ़कर 7.3 फीसदी हो गया था।

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेवा व्यापार और द्वितीयक आय खाते दोनों में उच्च अधिशेष नजर आया जिसने वस्तु व्यापार घाटे में हुई गिरावट से अधिक का योगदान किया। चालू खाते के घाटे की बाहरी भरपाई पर इस तरह की कम निर्भरता, पूंजी प्रवाह में उतारचढ़ाव और उससे जुड़ी मुद्रा विनिमय दर में अस्थिरता से बचाने में एक मजबूत बचाव की तरह काम करती है और वर्तमान वृहद आर्थिकी और भूराजनीतिक उथलपुथल के दौर में यह अपवाद नहीं बल्कि एक सामान्य स्थिति है।

व्यापार को लेकर बढ़ती अनिश्चितता ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। एसएंडपी ग्लोबल का अनुमान है कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2025 में धीमी होकर 2.9 फीसदी रह जाएगी। 2024 में यह 3.3 फीसदी थी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन और अमेरिका आगे बढ़ने के लिए जूझ रही हैं। यह बात भारत के निर्यात पर विपरीत असर डालेगी जबकि स्वस्थ घरेलू वृद्धि जो 6.5 फीसदी रह सकती है, वह आयात को बल देगी। तो क्या यह भारत के चालू खाते के लिए चिंता की बात है? उतनी नहीं।

इस वित्त वर्ष में हमें उम्मीद है कि चालू खाते का घाटा जीडीपी के करीब 1.3 फीसदी के साथ सुरक्षित स्तर में रहेगा। चालू खाते में न केवल वस्तु व्यापार शामिल है बल्कि प्राथमिक तथा द्वितीयक खातों के अधीन सेवा व्यापार और आय भी इसमें शामिल है। इनकी संभावनाओं पर चर्चा के पहले यह याद करना उचित रहेगा कि पहले सीएडी में तेज इजाफा क्यों हुआ था। वित्त वर्ष 12 और 13 में यह क्रमशः जीडीपी के 4.3 फीसदी और 4.8 फीसदी के स्तर पर था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देश का वाणिज्यिक वस्तु व्यापार घाटा दोनों साल 10 फीसदी से अधिक हो गया था। इससे बाद में वस्तु व्यापार घाटे में व्यापक कमी आई क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों और सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सेवा और द्वितीयक आय में इजाफा जीडीपी के 3.5 फीसदी के स्तर पर स्थिर रहा। अब हालात अलग हैं। अमेरिका द्वारा उच्च शुल्क लगाने की बात बताती है कि 2025 में भारत समेत तमाम देशों के लिए निर्यात संभावनाएं कमजोर रहेंगी। इस वर्ष के आरंभ में वैश्विक वस्तु व्यापार में जो इजाफा हुआ, वह इसलिए क्योंकि उच्च शुल्क दरों की आशंका में आयातकों ने अग्रिम खरीदारी की। यह सिलसिला जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का ताजा नए निर्यात ऑर्डर का सूचकांक घटकर 97.9 तक पहुंच गया है।

वित्त वर्ष 25 में देश का वस्तु निर्यात 441.8 अरब डॉलर के साथ स्थिर रहा। पिछले साल यह 441.2 अरब डॉलर था। इस वर्ष प्रतिकूल हालात बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ, चीन से आयात पर बढ़े हुए शुल्क से वहां अतिक्षमता और अपस्फीतिकारी दबाव बढ़ेगा, जिससे कारोबारी अतिरिक्त आपूर्ति भारत सहित अन्य बाजारों की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित होंगे। इसका एक अर्थ यह भी है कि मूल आयात पर ऊपर की ओर दबाव बना रहेगा तो फिर देश की दो प्रमुख आयात होने वाली जिंसों यानी कच्चे तेल और सोने का क्या होगा? कच्चे तेल की कीमतें जो पश्चिम एशिया में अनिश्चितता की वजह से बढ़ी हैं अब धीरे-धीरे कम हो रही हैं।

यह इजाफा अस्थायी था क्योंकि वैश्विक वृद्धि धीमी है और तेल की मांग में दीर्घकालिक कमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ा है। खास कर दुनिया के सबसे बड़े वाहन बाजार चीन में ऐसा हुआ है। उम्मीद है कि कच्चे तेल की कीमतें 65-70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास स्थिर होंगी जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये कीमतें 79 डॉलर प्रति बैरल थीं। ऐसे में कच्चे तेल का आयात ज्यादा दबाव नहीं डालेगा। इसी तरह कोयले की कीमतें भी कम हो सकती हैं। सोने की कीमतें जो पिछले वित्त वर्ष में डॉलर के संदर्भ में 30 फीसदी तक बढ़ी थीं, उनमें इस वर्ष और इजाफा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना एक खास संपत्ति वर्ग में आता है और निवेशकों के लिए सुरक्षित माना जाता है। यानी सोने की कीमतें अनिश्चित बनी रहेंगी। ऐसे में सोने के आयात पर कुछ दबाव रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि हाल के वर्षों में भारत में सोने की मांग कम हुई है। अक्सर कीमतें बढ़ने पर मांग घटती है। गत वित्त वर्ष में सोने के आयात में साल-दर-साल आधार पर 38 मीट्रिक टन की कमी आई और यह 757 मीट्रिक टन रह गया। हालांकि सरकार ने जुलाई में आयात शुल्क को 15 फीसदी से कम कर 6 फीसदी कर दिया था। कम मांग से देश के स्वर्ण आयात का डॉलर मूल्य भी नियंत्रित रहेगा। कुछ श्रेणियों में उच्च आयात और साथ ही वस्तु निर्यात के धीमा रहने का परिदृश्य देश के वस्तु व्यापार घाटे पर दबाव बढ़ा सकता है। यकीनन सेवा निर्यात जो कि कुल निर्यात में 48 फीसदी का हिस्सेदार है, वह एक बचाव मुहैया कराएगा। अमेरिका सॉफ्टवेयर निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है और वहां कुछ दबाव बन सकता है क्योंकि दुनिया की इस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में इस वर्ष धीमापन आ सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि बीते कुछ सालों में भारत का प्रदर्शन पेशेवर और प्रबंधन सलाह सेवा (पीएमसी) के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा है। इसमें वैश्विक क्षमता केंद्रों की भी भूमिका रही है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 21 और 25 के बीच जहां शुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात 14 फीसदी की दर से बढ़ा वहीं पीएमसी में 33 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

जहां तक धन प्रेषण की बात है, अमेरिका ने इस पर कर को पहले घोषित 3.5 फीसदी से कम करके 1 फीसदी कर दिया है। इससे राहत की स्थिति बनी है। इतना ही नहीं, चूंकि यह जनवरी 2026 से लागू होगा इसलिए इस वित्त वर्ष में इसका सीमित प्रभाव होगा। अमेरिका अब भारत में धनप्रेषण का सबसे बड़ा केंद्र है। हालांकि खाड़ी देश अभी भी इसमें अहम हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन वे अर्थव्यवस्थाएं तेल से होने वाली आय पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही हैं। तेल की कम कीमतों के कारण वहां से आने वाले धन पर अधिक असर पड़ता नहीं दिखता। संयुक्त अरब अमीरात भारत में धन भेजने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और 2024 में उसके जीडीपी में गैर तेल क्षेत्र का योगदान 75 फीसदी रहा।

ऐसे में देश के चालू खाते के घाटे में जहां इस वित्त वर्ष मामूली दबाव आ सकता है वहीं बड़ी चिंता का कोई कारण नहीं है। परंतु इसकी पूर्ति की निगरानी की जरूरत है। गत वित्त वर्ष में चालू खाते के घाटे में गिरावट के बावजूद वित्तीय प्रवाह अपर्याप्त था क्योंकि शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों में तेजी से कमी आई। हालांकि, शुद्ध विदेशी वाणिज्यिक उधारी से कुछ मदद मिली।

इस वित्त वर्ष भी विदेशी पूंजी प्रवाह के अस्थिर बने रहने की उम्मीद है क्योंकि विश्व स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है। उदाहरण के लिए विदेशी पोर्टफोलियो के डेट निवेश में से पहले तीन महीनों में काफी राशि बाहर गई है और बाह्य वाणिज्यिक उधारी भी शायद पिछले वर्ष जैसी नहीं रहे क्योंकि घरेलू ब्याज दरें कम हुई हैं।

बहरहाल, विदेशी मुद्रा भंडार के सहज स्तर पर रहने और चालू खाते के घाटे में मामूली इजाफे की आशंका के बीच भारत वैश्विक अनिश्चितता से निपटने की दृष्टि से बेहतर स्थिति में है।

(लेखक क्रिसिल में क्रमशः मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं)

औद्योगिक नीति को पुनर्स्थापित करने की दरकार

अतार्किक विकल्प

देवाशिष बसु

पहले दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माताओं को मुश्किल में डाला गया था। अब चीन ने विशेष उर्वरकों पर रोक लगा दी है। भारत में आने वाली जर्मनी की सुरंग-बोरिंग मशीन कथित तौर पर चीन में फंसी हुई है जिसके लिए निर्यात मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। अब इससे ज्यादा क्या होगा? भारत, दवाओं का एक बड़ा निर्माता देश है और अपनी प्रमुख दवा सामग्री का 80 फीसदी चीन से आयात करता है। सवाल यह है कि अगर इस पर भी रोक लग गई तब क्या होगा?

चीन को भारत से किसी भी महत्त्वपूर्ण चीज का आयात करने की जरूरत नहीं है जबकि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्से को चलाने के लिए हर साल चीन से 115 डॉलर अरब के सामान की जरूरत होती है। वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में राष्ट्र-निर्माण के लिए विनिर्माण को कम महत्त्वपूर्ण मानने वाले सभी लोगों को अब यह समझाना होगा कि चीन ने ऐसी स्थिति कैसे बना ली है कि वह किसी भी देश को नियंत्रित कर सकता है। इसका जवाब निश्चित रूप से स्थानीय विनिर्माण बढ़ाना है खासतौर पर सभी महत्त्वपूर्ण चीजों का और यह निश्चित रूप से हैरानी की बात होगी।

करीब 40 साल पहले, अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रमुख आर्थिक नुस्खा, मुक्त-बाजार सिद्धांतों का एक मिश्रण था जिसमें खुली प्रतिस्पर्धा, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, कम शुल्क बाधाएं और वित्तीय उदारीकरण जैसे पहलू शामिल थे। इसके कारण सरकार की योजनाओं पर मुक्त बाजार विचारधारा की निर्णायक बढ़त देखी गई। खैर, अब यह सोच पूरी तरह से बदल गई है। टैरिफ बाधाएं बढ़ गई हैं और सरकारी हस्तक्षेप आर्थिक ताकतों को मजबूती से आकार दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, स्टील से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाओं तक का विनिर्माण अपने देश में करना चाहते हैं।

उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो बाइडन ने सेमीकंडक्टर और हरित प्रौद्योगिकियों के लिए भारी सब्सिडी दी थी। ब्रिटेन विनिर्माताओं के ऊर्जा बिलों पर सब्सिडी देने पर विचार कर रहा है वहीं भारत ने 17 क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की है। इंडोनेशिया, विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश के तहत 'स्थानीय सामग्री' अनिवार्य कर रहा है और अपने विशाल निकल भंडार के साथ यह इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमुख केंद्र बनने की आकांक्षा रखता है।

औद्योगिक नीति' का विचार एक वक्त में सरकार की अक्षमता और भ्रष्टाचार की याद दिलाता था। वर्ष 1950 और 1970 के दशक के बीच, भारत की औद्योगिक नीति वास्तव में मूल्य नियंत्रण, लाइसेंसिंग, आयात प्रतिबंध और सार्वजनिक क्षेत्र के दबदबे का मिश्रण थी और यह एक ऐसा मॉडल था जिसने उद्यमशीलता को बाधित किया, अक्षमताओं को बढ़ावा दिया और भ्रष्ट सरकारी उद्यमों को समर्थन दिया जिन्होंने सरकारी खजाने को खाली कर दिया। ऐसे में सवाल उठ है कि फिर औद्योगिक नीति और इसके मुख्य घटक, विनिर्माण को अब वृद्धि के संदर्भ में क्यों तरजीह दी जा रही है?

इसका जवाब है चीन। क्या आपने यह नहीं देखा कि कैसे सोची-समझी औद्योगिक नीतियां किसी देश को बदल सकती हैं जैसे विश्व युद्ध से पहले जापान और बाद में ताइवान और दक्षिण कोरिया बदला? एक लंबी अवधि की औद्योगिक नीति कैसे तैयार की जाए और क्रियान्वित की जाए, इसका एक शानदार उदाहरण चीन पेश करता है। इसी नीति के बलबूते उसने वैश्विक स्तर के विनिर्माण के 32 फीसदी हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है, जिससे सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भी इसकी ताकत के सामने कमजोर हो गए हैं। इन रुझानों में आखिर भारत कहां मुफीद बैठता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत 2014 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की हिस्सेदारी 15 फीसदी से बढ़ाकर 2025 तक 25 फीसदी करने का वादा किया गया था, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि था। लेकिन प्रचार के नारों और रोडशो के अलावा कुछ खास नहीं हुआ।

इस दिशा में एक और व्यवस्थित प्रयास छह साल बाद, मार्च 2020 में किया गया जब भारत ने तीन क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की, जिसे बाद में 17 क्षेत्रों तक बढ़ाया गया। इसके पीछे मकसद घरेलू विनिर्माण क्षमता को 30 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना, आयात की जगह लेना और 60 लाख नई नौकरियों के मौके तैयार करना था।

पीएलआई योजना ने मोबाइल फोन असेंबल करने और दवा सामग्री के क्षेत्र में कुछ सफलता दिलाई है। फिर भी, घरेलू स्तर पर मूल्यवर्धन कम है, जिसमें प्रमुख घटक अब भी आयात किए जा रहे हैं। जनवरी 2024 में एक सरकारी विज्ञप्ति में दावा किया गया था कि इसके तहत रोजगार के 6,78,000नए मौके तैयार हुए। हालांकि यह एक ऐसे देश में बेहद कम संख्या है जहां सालाना 1 करोड़ से अधिक युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं।

जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी वास्तव में और कम हो गई है और यह वर्ष 2020 के 15.4 फीसदी से घटकर 2025 में 14.3 फीसदी रह गई है। रॉयटर्स की एक जांच में आंतरिक सरकारी दस्तावेजों का हवाला दिया गया था जिससे पता चला है कि अक्टूबर 2024 तक पीएलआई आवंटित फंड का 8 फीसदी से भी कम हिस्सा वितरित हुआ था। इसके अलावा, योजना के दो-तिहाई लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ?

पीएलआई योजना में गलत प्राथमिकताओं पर काम किया जा रहा है। दर असल, जिन बुनियादी बातों पर पहले ध्यान देना चाहिए, वे हैं शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता, साथ ही व्यापार करने में आने वाली भारी लागतें जिनमें लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, कर और उपकर, रिश्वत, राज्य व केंद्रीय कानून और लालफीताशाही शामिल हैं। यही वजह है कि चमड़ा, कपड़े, हस्तशिल्प और आभूषण जैसे अधिक श्रम वाले क्षेत्र भी बड़े पैमाने पर विकसित नहीं हो पाए हैं। यह योजना हमें याद दिलाती है कि शॉर्टकट तरीके से औद्योगिक क्षमता नहीं तैयार की जा सकती है। असली विनिर्माण तंत्र बनाने में वर्षों के बुनियादी सुधार की दरकार होती है।

भारत के लिए इस नींव को तैयार करने के प्रयास कम ही हुए हैं। वर्ष 2000 के दशक के मध्य में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों की निर्यात-आधारित सफलता की नकल करने की कोशिश की, जिसके लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को बढ़ावा दिया गया। लेकिन यह पहल भ्रष्टाचार, विवाद और घोटालों में उलझ कर आखिरकार नाकाम हो गई। इसमें नागपुर के पास भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को 1,000 एकड़ जमीन का आवंटन जैसे उदाहरण भी शामिल हैं।

भारत ने अक्टूबर 2021 में 'गति शक्ति' योजना शुरू किए जाने तक व्यवस्थित रूप से लॉजिस्टिक्स लागत कम करने की कभी कोशिश नहीं की। लॉजिस्टिक्स लागत कम करने (जो अभी जीडीपी का 13-14 फीसदी है जबकि चीन में यह 8-10 फीसदी है) के अलावा, इसका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भी है।

अगर भारत में विनिर्माण क्षेत्र तरक्की करता तब यह रोजगार की कमी और गरीबी की दोहरी चुनौतियों से निपट सकता था। सेवाओं के विपरीत, विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी संख्या में अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक खप सकते हैं। लेकिन इस मजबूत आधार को बनाने के बजाय, सरकार ने कई नकद हस्तांतरण और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि ये योजनाएं अशांति-हलचल रोक सकती हैं और राजनीतिक लाभ दे सकती हैं पर ये काम करने की प्रेरणा भी कम करती हैं, खासतौर पर ग्रामीण भारत के क्षेत्र में। विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियां लगातार कामगारों की कमी की शिकायत करती हैं, जबकि देश में बेरोजगारी बहुत अधिक है। वास्तव में भारत की युवा आबादी के होने के फायदे तेजी से आबादी के बोझ में तब्दील हो रहे हैं।

छोटे उद्योग क्षेत्रों की स्थिति बेहद खराब है, जहां ज्यादातर लोग काम करते हैं और ये एक दमघोंटू माहौल में संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी औद्योगिक नीति तभी अच्छी होती है जब उसे ठीक तरीके से लागू किया जाए और उसे सहारा देने वाले दूसरे सुधार भी हों। यह बात 40 साल पहले भी उतनी ही सच थी जितनी आज है।

(लेखक मनीलाइफडॉटइन के संपादक और मनीलाइफ फाउंडेशन में ट्रस्टी हैं)

आपका पक्ष

दुर्लभ खनिजों पर चीन का व्यवधान

ब्रिक्स सम्मेलन में दुर्लभ खनिजों को हथियार न बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान और चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर रोक लगाने के समाचार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में चिंताजनक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 80 वर्ष के कार्यकाल में आर्थिक, व्यापारिक, सामरिक, राजनयिक, सामाजिक, क्षेत्रीय संगठनों का गठन हुआ और कितने ही ऐसे संगठन अपने उद्देश्यों में असफल होकर लुप्त हो गए। इसके मूल में यही कारण है कि चीन और अमेरिका अपने आर्थिक, सामरिक, व्यापारिक हितों की स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे संगठन खड़े करते हैं। जिस संगठन में चीन सदस्य होगा वहां कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह अपने व्यापारिक हितों की तिलांजलि देकर दुर्लभ खनिजों पर प्रतिबंध हटा लेगा या निर्यात से रोक हटा लेगा। ब्रिक्स संगठन की भी स्थिति ऐसी ही है। वर्तमान में विश्व के सभी देशों के उद्योग दुर्लभ खनिजों की बाधित आपूर्ति श्रृंखला से जूझ रहे हैं। विडंबना यह है कि अप्रीकी देशों में खनिज भंडार हैं, जिनके दीर्घकालिक समझौते चीन के साथ हैं और हम खनिजों के मूल स्रोत वाले देशों को छोड़कर चीन के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में खनिजों की कोई कमी है परंतु इस ओर गंभीर प्रयास नहीं किए गए। आज जैसे कच्चे तेल उत्पादक देशों का वर्चस्व समाप्त हो रहा है, वैसे ही एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स और दुर्लभ खनिजों के वर्चस्व वाले देशों के साथ भी हो सकता है यदि इनके विकल्पों पर लक्ष्यनिष्ठ होकर शोध किए जाएं।

विनोद जौहरी, दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ब्रिक्स सम्मेलन के सत्र में पर्यावरण, कॉप 30 तथा वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा की थी

आरडीआई योजना से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा

विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाएं शोध और विकास (आरऐंडडी) में सक्रिय निवेश करती हैं, जिससे वे नई तकनीकों, उत्पाद और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनती हैं। भारत में शोध पर सरकारी निवेश तो होता रहा है, लेकिन निजी क्षेत्र की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है। इससे स्टार्टअप, नई टेक्नॉलजी और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए नवाचार को जरूरी गति नहीं मिल पाई। वर्तमान में हमारा देश आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जहां नवाचार और प्रौद्योगिकी का बड़ा योगदान है। ऐसे में शोध, विकास और नवाचार में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस नीति और वित्तीय सहायता की दरकार थी। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शोध और नवाचार को मजबूती देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की 'शोध, विकास और नवाचार' (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र को कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के लिए फंडिंग दी जाएगी। यह वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के रूप में होगा, जिससे स्टार्टअप और कंपनियों को नवाचार, शोध और उत्पाद विकास के लिए जरूरी पूंजी मिल सके।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

सिक्किम सरकार ने राज्य के पांच जिलों के बड़े बाजारों में सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों को स्तनपान कराने के लिए छह 'स्तनपान पॉड' स्थापित किए हैं। राज्य के महिला, बाल, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग कल्याण एवं विकास विभाग ने हाल में पाक्योंग जिले के पाक्योंग बाजार में 'स्तनपान पॉड' का उद्घाटन किया था।

ब्रिक्स सम्मेलन

राजनयिक विजय

ब्रिक्स सम्मेलन भारत की राजनयिक विजय है। उसने आतंकवाद की घोर निन्दा करते हुए टैरिफ और विश्व व्यापार पर भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया। भारत के लिए ब्राजील के रियो में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन बहुत लाभदायक रहा। इसने आतंकवाद और टैरिफ पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया जो भारत तथा 'वैश्विक दक्षिण' के लिए प्रमुख चिन्ता का विषय हैं। ब्रिक्स सम्मेलन से सर्व-सहमति से ज्यादा समतापूर्ण विश्व व्यापार परिवेश के प्रति अपने सरोकार व्यक्त किए। रविवार को एक प्रभावशाली घोषणापत्र में ब्रिक्स देशों-ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने 'कठोरतम शब्दों में' पहलगाम आतंकी हमले की निन्दा करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। हालांकि, इस दस्तावेज में खासतौर से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, पर 'सीमापार से आतंकवाद', 'आतंकी फाइनैंसिंग' तथा 'सुरक्षित स्वर्गों' जैसे शब्दों ने भारतीय दृष्टिकोण मजबूती से रखते हुए इस्लामावाद की निन्दा की जिसने गैर-राज्य कारकों का प्रयोग आतंकी कृत्य में तथा राजनय के औजार के रूप में किया है। वास्तव में यह संतुलित घोषणापत्र था जिसने आतंकवाद पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए इसे किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या नस्ली समूह से नहीं जोड़ा है। नई दिल्ली ने लंबे समय से इस सिद्धान्त का समर्थन कर उसे उचित ठहराया है। भारत का अटूट विश्वास है कि आतंकवाद का कोई धर्म या राष्ट्रीयता नहीं है और यह मानवता के खिलाफ अपराध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए दृढ़ता से कहा, 'आतंकवाद की निन्दा सिद्धान्त का मामला होना चाहिए, सुविधा का नहीं। यदि हमारी प्रतिक्रिया कहीं और किसके खिलाफ हमला हुआ पर निर्भर करेगी तो यह स्वयं मानवता के साथ धोखा होगा।'

इस एक वाक्य से प्रधानमंत्री ने चीन को परोक्ष चेतावनी दी जिसने अनेक अवसरों पर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्रसंघ की कार्रवाई में बाधा डाली है। मोदी ने ज्यादा स्पष्ट वैश्विक कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा, 'आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के पीड़ितों और उसके समर्थकों को समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता है।' ब्रिक्स घोषणा ने इस भावना का साझा करते हुए आतंकवाद के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' को रेखांकित किया। इसमें सभी देशों का आह्वान किया गया है कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वाह करें। इसे चीन को सीधी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है जिसके द्वारा संरा. में पाकिस्तान के राजनयिक बचाव के कारण भारत के आतंकवाद-विरोधी प्रयासों को बार-बार धक्का लगा है। ब्रिक्स सम्मेलन की एक और उपलब्धि विश्व व्यापार पर उसका दृष्टिकोण है। व्यापार के संबंध में सम्मेलन ने अनुचित टैरिफों पर भारत का दृष्टिकोण स्वीकार करते हुए न्यायोचित विश्व व्यापार व्यवस्थाओं की आवश्यकता बताई। नेताओं ने कुछ विकसित देशों व खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई अति-संरक्षणवाद और एकपक्षीय व्यापार पर भारत की चिन्ताओं का समर्थन किया। सम्मेलन ने स्पष्ट रूप से एक समान आधार की वकालत की और उसने अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रचारित टैरिफ व्यवस्था की निन्दा की। लेकिन ट्रंप ने भी इस पर त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि ब्रिक्स के साथ जुड़ने वाले देशों को दस प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ देना पड़ेगा। इस प्रकार कुल मिला कर ब्राजील के ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को एक मजबूत मंच प्रयोग करने का अवसर मिला और उसके अनेक विचारों और दृष्टिकोणों को वैधता मिली। ब्रिक्स सम्मेलन ने आतंकवाद से लेकर न्यायोचित व्यापार तक नई दिल्ली के सरोकारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिली। ब्रिक्स के अंतिम घोषणापत्र में इनको शामिल किया जाना इस वैश्विक मंच पर भारतीय राजनय की नैतिक विजय है। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाग नहीं लिया और रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने भी इसे वर्चुअल रूप से संबोधित किया जिससे मीडिया में मोदी की उपस्थिति अधिक अनुभव की गई।

वन महोत्सव का महत्व

वन महोत्सव, 2025 का तात्कालिक महत्व आज बहुत अधिक है। 1950 में के.एम. मुंशी द्वारा शुरू पेड़ लगाने की इस पहल का विकास आज देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन में हो गया है।

सत्येन्द्र सिंह
(लेखक, आपदा प्रबंधन से संबद्ध हैं)

भारत द्वारा आयोजित वन महोत्सव, 2025 का तात्कालिक महत्व आज पहले के किसी भी समय की तुलना में अधिक है। 1950 में के.एम. मुंशी द्वारा शुरू पेड़ लगाने की इस पहल का विकास आज देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन में हो गया है। हर साल पहली जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव या 'पेड़ों के उत्सव' का आयोजन होता है। तत्कालीन कृषि केन्द्रीय मंत्री के.एम. मुंशी द्वारा 1950 में इसकी शुरुआत वन संरक्षण को प्रोत्साहित करने तथा पर्यावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई थी।

पिछले दशकों में यह भारत का एक सर्वाधिक प्रभावशाली परिस्थितिकी अभियान बन गया है जो हमारे जीवन में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता पैदा करता है। 2025 में जब दुनिया और भारत को बढ़ती जलवायु चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यह आयोजन तात्कालिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वर्ष की थीम- 'मजबूती के लिए पेड़ लगाएं' इस तथ्य को रेखांकित करती है कि पेड़ न केवल प्रकृति का हरित श्रृंगार हैं, बल्कि वे हमारे संरक्षक भी हैं। वे हमारे घरों, खेतों, जल संसाधनों, शहरी परिदृश्यों तथा अंततः हमारे जीवन की रक्षा करते हैं।

मानसून का मौसम एक बार फिर भयानक विनाश लाया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं से ग्रस्त हैं। पहाड़ियां ढह रही हैं, नदियों में बाढ़ आ रही है तथा पूरे-पूरे समुदायों को विस्थापित होना पड़ा है। इसके साथ ही मध्य, पश्चिम व दक्षिण भारत विलंबित या अनुपयुक्त बरसात का सामना कर रहा है जिसके कारण सूखे, गिरते जल स्तर, फसलों की बरबादी और घटते भूमिगत जल जैसी समस्यायें पैदा होती हैं। इस प्रकार कुछ क्षेत्रों में बाढ़ तथा दूसरे क्षेत्रों में सूखा हर साल आते रहते हैं। इस असंतुलन का कारण पर्यावरण क्षरण व खासकर विकास, खनन, सड़क निर्माण व बेलगाम शहरीकरण है। पानी सोखने, सतह पर जल बह जाने से रोकने तथा मिट्टी को बांधे रखने वाले पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जंगलों की कटाई होती है तो बरसात का पानी बिना नियंत्रण के बंजर भूमि में फैल जाता है जो भू-क्षरण, भूस्खलन तथा बाढ़ का कारण बनता है। शहरों में पेड़ों की कमी से नालियां बंद हो जाती हैं, अचानक बाढ़ आती है तथा तापमान बढ़ता है। गांवों में इसके कारण सूखा गंभीर होता है तथा मृदा की उर्वरकता प्रभावित होती है।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत की 60 प्रतिशत भूमि प्राकृतिक आपदाओं का संकट झेल सकती है। 'विब्स रे कैटास्ट्राफ रिपोर्ट' के अनुसार भारत को प्राकृतिक आपदाओं के कारण केवल 2023 में ही 12 बिलियन डालर का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि एक दशक पहले यह नुकसान 8 बिलियन डालर था। इस संदर्भ में पेड़ लगाना केवल पर्यावरण गतिविधि से आगे बढ़ कर जीवनरक्षक रणनीति है। पेड़ प्राकृतिक ढांचागत संरचना की तरह काम करते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को स्थिर रखती हैं, बरसात का पानी सोखती हैं, भूस्खलन का खतरा कम करती हैं, हवा को शुद्ध करती हैं, तापमान घटाती हैं तथा भूमिगत जल का संभरण करती हैं।

पेड़ खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा विभीषिकाओं से सर्वाधिक प्रभावी बचाव हैं। ओडिसा के मैंग्रूव वन इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1999 के विनाशकारी भयानक समुद्री तूफान में मैंग्रूव वनों से संरक्षित गांवों को इससे वंचित गांवों की तुलना में बहुत कम नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद से ओडिसा ने बड़े क्षेत्र में मैंग्रूव वनों को बहाल किया जिन्होंने 2013 में फालिन और 2019 में फानी जैसे समुद्री तूफानों से व्यापक सुरक्षा प्रदान की। शोध से पता चलता है कि एक हेक्टर मैंग्रूव वन लहरों की ऊर्जा को 60 प्रतिशत तक घटा देते हैं और इस प्रकार समुदायों को विनाशकारी समुद्री लहरों तथा तूफानी हवाओं से सुरक्षा देते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में निर्वनीकरण के कारण ढलानों से भूस्खलन बढ़े हैं।

इसके साथ ही खासकर सेना द्वारा समर्थित इको-टास्क फोर्स द्वारा किए जाने वाले वनीकरण अभियानों से बंजर पहाड़ियों को फिर से हरा-भरा बनाने में मदद मिली है। ओक, पाइन व बांस जैसे स्वदेशी पेड़ों के लगाने से ढलानों को स्थिर बनाने तथा भूक्षरण रोकने में सहायता मिली है। अध्ययनों से स्पष्ट है कि पेड़ों से आच्छादित गांवों में मानसून संबंधी नुकसान झेलने की क्षमता पैदा हो जाती है।

मराठवाड़ा तथा राजस्थान के कुछ सूखा-संभावित क्षेत्रों में कृषिवानिकी ने परिवर्तकारी बदलाव किए हैं। नीम, मोरिंगा या अमलतास जैसे पेड़ों को फसलों के साथ लगाने से मृदा में नमी बढ़ती है, फसल ज्यादा स्थाई होती है तथा सूखे से बेहतर ढंग से बचाव होता है। ये पेड़ फल, चारा और छाया प्रदान करने के साथ भूमिगत जल संभरण में भी सहायक होते हैं। कुछ मामलों में किसानों ने कृषिवानिकी व्यवहारों से फसल की उत्पादकता में 30 प्रतिशत तक वृद्धि देखी है। शहरी भारत भी वायु प्रदूषण के कारण बढ़ते तापमान का शिकार है। 2024 में अनेक शहरों को 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड के भयानक तापमान का सामना करना पड़ा जिससे लू लगने के कारण अनेक मौतें हुईं। शहरों में पेड़ प्राकृतिक एयरकंडीशनरों का काम करते हैं और अपने आसपास के क्षेत्रों का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करते हैं।

हरित शहरी स्थलों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 2020 में 'नगर वन योजना' शुरू की थी जिसके अंतर्गत शहरों में 1,000 'नगर वन' लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इस कार्यक्रम में समुदायों, स्थानीय संस्थाओं, एनजीओ तथा शिक्षा संस्थानों को स्वच्छ, हरे-भरे और स्वस्थ शहर बनाने हेतु सक्रिय सहभागिता निभाने को प्रेरित किया गया था। भारत की व्यापक जलवायु प्रतिबद्धताओं में वनों की बहाली पर भी जोर दिया गया है। 'पेरिस समझौते' के अंतर्गत भारत ने वनों और वृक्षों का आच्छादन बढ़ाने के माध्यम से 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन कार्बनडाई आक्साइड कार्बन सिंक द्वारा घटाने की प्रतिज्ञा की थी।

'द इंडिया स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 2023' से पता चलता है कि देश की 25.17 प्रतिशत से अधिक भूमि वनों या वृक्षों से आच्छादित है जो 30.43 बिलियन टन कार्बन डाईआक्साइड के कार्बन सिंक के बराबर है। 'ग्रीन इंडिया मिशन' तथा 'कंपेंसेटरी एफारेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथारिटी'-कैम्पा जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य पूरे देश में वनीकरण प्रयासों को मजबूत करना है। लेकिन भारत को हरा-भरा बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार पर नहीं डाली जा सकती है, बल्कि इसे एक सामूहिक आंदोलन में विकसित करना होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2024 में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान शुरू किया है।

इसने करोड़ों लोगों को एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने को प्रेरित किया है। इससे वृक्षारोपण एक गहरा व्यक्तिगत व समुदाय-केन्द्रित अभियान बन गया है। पूरे भारत के शिक्षा संस्थान 'स्कूल नर्सरी योजना' तथा 'इको क्लब' के माध्यम से छात्रों में पर्यावरण चेतना जगा रहे हैं।

गांवों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियां स्थानीय लोगों के सहयोग से खराब हुए जंगलों को सुधार रही हैं। अनेक ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए वन उनकी जीवनरेखा होते हैं जो उनको भोजन, जड़ी-बूटियां, बांस तथा अन्य आवश्यक चीजें देते हैं। वनों के बढ़ने से जल की उपलब्धता में सुधार आता है, कृषि को बढ़ावा मिलता है तथा आपदा का मुकाबला करने की क्षमता पैदा होती है। इस वर्ष वन महोत्सव मानते समय हमें प्रतीकात्मक कार्यों से आगे बढ़ना चाहिए।

वृक्षारोपण समुचित विचारों और संदर्भ के साथ होना चाहिए। इसके लिए देशी प्रजातियों का चयन होना चाहिए जो स्थानीय मिट्टी तथा जलवायु स्थितियों के अनुकूल हों तथा पौधों की देखभाल सुनिश्चित की जानी चाहिए। इनकी कम से कम दो से तीन साल तक देखभाल से उनका जीवन और विकास सुनिश्चित होता है। आज लगाया हर पौधा पर्यावरण, भावी पीढ़ियों तथा स्वयं अपने से किया एक वादा है। पेड़ हमारे रक्षा कवच, जीवनरेखा तथा विरासत हैं। इस वन महोत्सव को हर स्कूल, सड़कों के किनारों, खेतों तथा बंजर पहाड़ियों को सुधारने का प्रयास होना चाहिए। हर पेड़ हमारे लिए हरित, सुरक्षित तथा ज्यादा सुनिश्चित भविष्य का वादा है।

तकनीक चलित जगत में मानवीय स्पर्ष

> ये मशीनें केवल उतनी ही अच्छी हो सकती हैं, जितना कि उन्हें प्रोग्राम किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है और उनमें सुधार किया जाता है।

संजय चंद्रा
(लेखक, रेलवे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं)

प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में अकल्पनीय तरीके से क्रांति ला दी है। शुरुआत में बदलाव की गति भले ही धीमी रही हो, लेकिन पहले रखी गई नींव ने यह सुनिश्चित किया है कि सदी की शुरुआत से ही इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि, हाल ही में हुई कुछ घटनाओं ने मुझे एहसास दिलाया कि ये मशीनें केवल उतनी ही अच्छी हो सकती हैं, जितना कि उन्हें प्रोग्राम किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है और उनमें सुधार किया जाता है।

एक सप्ताहांत, हमने एक प्रमुख खाद्य वितरण ऐप के माध्यम से रात का खाना मंगवाया। हमारा ऑर्डर रसोई द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और जल्द ही, डिलीवरी पार्टनर भी नियुक्त कर दिया गया। मैंने डिलीवरी बॉय को कॉल किया, जो अपेक्षित डिलीवरी समय के बाद भी रेस्तरां के स्थान पर स्थिर रहा। सवार ने पुष्टि की कि वह भोजन लेने के लिए रेस्तरां से कॉल का इंतजार कर रहा था। संपर्क नंबर पर रेस्तरां पहुंच योग्य नहीं था जिसे मैं केवल ऐप के माध्यम से डायल कर सकता था। अब तक, डिलीवरी का समय भी संशोधित किया जा चुका था। बेंगलौर में हेल्पलाइन पर कॉल करने के परिणामस्वरूप उन्होंने उसी पहुंच योग्य नंबर पर कॉल किया।

ऑर्डर तुरंत रद्द कर दिया गया, और पैसे वापस कर दिए गए। एक और बार, उसी प्लेटफॉर्म पर स्थित रेस्तरां ने सवार को भोजन सौंपने की पुष्टि की। इस बार, वह पहुंच से बाहर था। मुझे एक संदेश मिला कि अगले कुछ मिनटों में डिलीवरी की जाएगी, भले ही ऐप पूरे समय डिलीवरी बॉय को रेस्तरां के पास एक ही स्थान पर दिखा रहा था। कुछ दिनों बाद, मैंने एक प्रमुख दवा वितरण ऐप के माध्यम से एक आयुर्वेदिक दवा का ऑर्डर दिया। एक अपेक्षित डिलीवरी समय तुरंत दिया गया था, जो वास्तविक डिलीवरी तक भी प्रदर्शित होता

रहा - लगभग तीन घंटे बाद। एक प्रमुख राष्ट्रीय एयरलाइन ने भी यात्रियों के लिए एक समान इंटरफेस विकसित किया है। यह प्लेटफ़ॉर्म लगभग वास्तविक समय के अपडेट प्रदान करता है। रायपुर से दिल्ली के लिए मेरी हाल की उड़ान परिचालन संबंधी मुद्दों के कारण कुछ घंटों की देरी से हुई। ऐप आने वाली उड़ान की स्थिति को टैक्सीइंग के रूप में प्रदर्शित करता रहा। मैं यह नहीं समझ पाया कि यह प्रस्थान करने वाले या आने वाले हवाई अड्डे पर है।

बोर्डिंग डेस्क पर कोई कर्मचारी नहीं था। लंबे समय तक फोन पर या घोषणाओं के माध्यम से कोई अपडेट नहीं था। मैं आधी रात के बाद उतरा क्योंकि मैं एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी था। ये अलग-अलग मामले नहीं हैं। ड्राइवरों द्वारा केब रद्द करने के कई उदाहरण हैं। कई लोगों को अन्य प्लेटफार्मों के साथ अप्रिय अनुभव हुए हैं। ऐसे सभी मामलों में संदेश हेल्पडेस्क कार्यकारी द्वारा पुष्टि किए बिना स्वचालित होते हैं।

किसी कार्यकारी या ऐप पर संबंधित पक्षों द्वारा सकारात्मक पुष्टि, डिफ़ॉल्ट के मामले में प्रतिकूल परिणामों के साथ, समाधानों में से एक हो सकता है। मेरे 95 वर्षीय पिता कभी-कभी निराश हो जाते हैं जब वे अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन पर कोई फ़ाइल नहीं ढूँढ पाते हैं। वह इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दोषी ठहराते हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि गैजेट और वर्चुअल सेवाएँ वही करेंगी जिसके लिए उन्हें बनाया गया है।

इन आधुनिक गैजेट और ऐप का उद्देश्य हमारे जीवन को सरल बनाना है, न कि इसे इस तेज़-तर्रार दुनिया में पहले से ही झेल रहे दैनिक तनाव से परे जटिल बनाना। मुझे निश्चित रूप से खुशी होगी अगर कोई हेल्पडेस्क कार्यकारी मुझसे संपर्क करे, माफ़ी मांगे और सेवा में कमी के लिए मुझे मुआवजा दे, बिना मुझे कोई पहुंच से बाहर नंबर डायल करने या बहुत व्यस्त नंबर डायल करने की ज़रूरत पड़े जो कई प्रयासों और कई कुंजियों को दबाने के बाद कनेक्ट होता है। यह असंभव नहीं है।

हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर के माध्यम से,ड्ड हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो गया है। मैं पाता हूं कि मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल और इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी ऐसे उत्पाद या सेवा के बारे में फीड और विज्ञापनों से भरे पड़े हैं, जिस पर मैंने किसी प्लेटफॉर्म पर क्षणभंगुर नज़र डालने के अलावा थोड़ा अधिक समय बिताया हो। मुझे संदेह है कि एआई हमारी आवश्यकताओं को पकड़ लेता है — यहां तक कि हमारी बातचीत में भी घुसपैठ करता है। एक दिन, मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ चर्चा कर रहा था।

अगली बार जब मैंने अपना मोबाइल खोला, तो मुझे उक्त उत्पाद के बारे में बहुत सारी फीड मिलीं। मनुष्य पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास आत्मचिंक विकसित बुद्धि है जो मानव जाति के लिए आरामदायक जीवन के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है। एक प्रशिक्षित बैंकएंड अधिकारी का उपयोग न केवल घबराई हुई नसों को शांत करने के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि सॉफ्टवेयर और मशीन सुधार के लिए फीडबैक तंत्र के रूप में भी किया जाना चाहिए। यह एक निवेश करने लायक होगा और इसे अनावश्यक खर्च के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

आप की बात

एलन मस्क की पार्टी

एलन मस्क ने पहले डोनॉल्ड ट्रम्प को खूब मस्का लगाकर राष्ट्रपति का चुनाव जितवा दिया। अब दोनों में मतभेद इतने तेजी से उभर रहे हैं कि एक-दूसरे को वे फूटी आँख नहीं सुहा रहे हैं। ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर सब्सिडी बंद हुई तो मस्क को अमरीका से बिस्तर-बोरी बांधकर मूल देश दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ेगा। जबकि मस्क ने यहीं रहकर उनके विरुद्ध नई अमरीका पार्टी बनाकर उनसे बदला लेने की योजना बना ली है। साथ ही एक सर्वे में उन्होंने जनता का समर्थन भी पा लेने की बात की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को दो भ्रष्ट पार्टियों-डेमोक्रेट व रिपब्लिकन से निजात दिलाना है। वैसे अमरीका का इतिहास रहा है जब-जब भी किसी ने तीसरी राजनीतिक पार्टी बनाई, वह थोड़े समय बाद ही खत्म हो गई। अब देखना है एलन मस्क की अमरीका पार्टी कितने समय जीवित रह पाती है और अमेरिका को दोनों पार्टियों से आजाद करवाने में कितनी सफल होती है या फिर मस्क को डोनॉल्ड ट्रम्प अमेरिका से आजाद करके साऊथ अफ्रीका पहुँचाने में कितने सफल होते हैं। वैसे भी किसी सशक्त व्यक्ति द्वारा प्रत्याशी को सपोर्ट करके जितवा देना अलग बात होती है और नई पार्टी बनाकर सफलता पाना बिल्कुल अलग। यह सत्ता और पूंजी अथवा कुछ पूंजीपतियों से दूसरे पूंजीपतियों की लड़ाई है।

-शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

विवादों में घिरे ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में अनेक विवाद और नीतिगत असमंजस देखने को मिले हैं। उनके शुरुआती एजेंडे प्रवासी संकट, व्यापार घाटा, आर्थिक सुधार और अंतरराष्ट्रीय सैन्य टकराव का अंत, आदि सभी में से उलझे ही नजर आए हैं। टैरिफ को लेकर उन्होंने जो डेडलाइन दी थी वह बीतने को है लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं दिखता। उलटे वह एक बार फिर धमकी और दादागिरी की भाषा पर उतर आए हैं। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अनिश्चितता और विफलता से भरा रहा है। प्रवासियों को लेकर उनके कठोर रवैये ने कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में असंतोष फैला दिया। उनका तथाकथित मेक अमेरिका ग्रेट अगेन खुद शायद उनकी पार्टी के कई नेताओं को भी स्वीकार्य नहीं है। यह दशाता है कि उनके नीतिगत फैसले एकपक्षीय और अपरिपक्व हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अमेरिका की छवि को गहरा आघात पहुंचा है। उनकी धमकी भरी भाषा और व्यापार में आक्रामक रवैये ने सहयोगी देशों से संबंधों को नुकसान पहुंचाया है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि ट्रंप पर यह आरोप बार-बार लगे हैं कि वे राष्ट्रीय नीतियों को अपने निजी व्यापारिक हितों के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं।

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

सटीक मतदाता सूची

जिस लोकतंत्र की नींव एक व्यक्ति- एक वोट के सिद्धांत पर टिकी हो वहां यदि एक मृत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में हो या एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज हो तो यह केवल तकनीकी चूक नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। 2024 तक भारत में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 96.8 करोड़ से अधिक हो चुकी हैए लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें से लगभग 3 करोड़ नाम या तो दोहराए गए हैं, फर्जी हैं या अपर्याप्त रूप से सत्यापित हैं। यह स्थिति न केवल निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को संकट में डालती हैए बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक छवि पर भी सवाल उठाती है। चुनाव आयोग द्वारा आधार लिंकिंग, डिजिटल संशोधन और फिंजिकल वेरीफिकेशन जैसे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी वास्तविकता में यह प्रयास अभी भी अपूर्ण और कमजोर हैं। तकनीकी सीमाएं, प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक हस्तक्षेप इन सुधारों को बाधित कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि मतदाता सूची को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोमेट्रिक जांच और स्थानीय सामाजिक निगरानी के जिस्तरीय ढांचे से साफ़ और प्रमाणित किया जाए ताकि वोट देना एक अधिकार रहे, कुछ राजनीतिक दलों का सत्ता तक पहुंचने का हथियार न बने।

-अवनीश गुप्ता, आजमगढ़

नए आपराधिक कानून

नए आपराधिक कानूनों की स्वीकार्यता व इनके बाद हुए सुधारों की बहुत चर्चा हो रही है। भारत में लागू नए आपराधिक कानून एक सकारात्मक और सुविचारित बदलाव के प्रतीक हैं। ये न केवल विधि के सिद्धांतों को आधुनिक संदर्भ में परिभाषित कर रहे हैं, बल्कि न्याय प्रक्रिया को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और पारदर्शी भी बना रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे प्रावधानों ने प्रक्रिया संबंधी कानून में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। अब ई-एफआईआर और जीरो एफआईआर जैसे तंत्र आम नागरिक को बिना थाने जाए न्याय तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं। जांच प्रक्रिया में तकनीक का समावेश भी उल्लेखनीय है। स्मार्ट डिवाइस, वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाएं और मोबाइल फॉरेंसिक लैब जैसे प्रयास आधुनिक और त्वरित न्याय की दिशा में उठाए गए साहसिक कदम हैं। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने इस बदलाव को प्रभावी ढंग से अपनाया है जिससे पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी है। किन्तु इनके साथ ही व्यवस्था की पुरानी खामियां बनी हुई हैं जिनको दूर करना जरूरी है।

- विभूति बुपक्या, खाचरौद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
शांति के बिना समृद्धि संभव नहीं

चुनाव आयोग की सख्ती

बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की आवश्यक पहल के खिलाफ भ्रामक और गुमराह करने वाले वीडियो एवं पोस्ट पर चुनाव आयोग की सख्ती आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। यह ठीक है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची के सत्यापन संबंधी फर्जी पोस्ट एवं वीडियो को खोज-खोज कर उन्हें गलत बता रहा है और इसी के साथ सच्चाई भी बयान कर रहा है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग को ऐसे भ्रामक वीडियो एवं पोस्ट करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। यह और कुछ नहीं सीधा-सीधा फेक न्यूज का मामला है। यदि इस तरह की फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो शरारती तत्वों का दुस्साहस और अधिक हो बढ़ेगा। ऐसे तत्व चुनाव आयोग के साथ-साथ भारतीय लोकतंत्र की छवि खराब करने का ही काम करेंगे। अतीत में करते भी रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि वे किस तरह ईवीएम के खिलाफ गुमराह करने वाले वीडियो साझा कर चुके हैं। समस्या यह है कि चुनाव आयोग के पास पर्याप्त अधिकार नहीं। वह खुद को और चुनाव प्रक्रिया को बदनाम एवं देश की जनता को गुमराह करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं कर पाता। यह सहज ही समझा जा सकता है कि बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया के खिलाफ कौन लोग भ्रामक पोस्ट एवं वीडियो साझा करने में लगे हुए हैं। यह तय माना जाना चाहिए कि इनमें से कई विपक्षी दलों के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक होंगे। आखिर यह एक तथ्य है कि कांग्रेस, राजद समेत कई विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन का बेतुका विरोध किया है।

समझना कठिन है कि आखिर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिए यह क्यों नहीं पता लगाया जाना चाहिए कि वास्तविक मतदाता कौन हैं। यह काम तो पूरे देश में होना चाहिए। पहले होता भी रहा है। इसको अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन संबंधी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। इनमें वकील एवं नेता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं। कपिल सिब्बल सदैव ऐसा करने में आगे रहते हैं। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा भी आगे आई हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कोई भी खटखटा सकता है, लेकिन क्या महुआ मोइत्रा बिहार की सांसद हैं? क्या उन्हें यह लगता है कि बिहार की तरह बंगाल में भी मतदाता सूची का सत्यापन हो सकता है। जो भी हो, ऐसा सत्यापन पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि सही मतदाता सूची से ही लोकतंत्र सशक्त बनेगा। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं के पीछे के असल इरादों को भांपे।

निखरेगी प्रतिभा

बिहार में शिक्षा परियोजना परिषद की कोशिश सरकारी स्कूलों के बच्चों की प्रतिभा को निखारने की है। इन बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। जाहिर है, इसके लिए सामान्य पाठ्यक्रम से अलग पाठ्य सामग्री की आवश्यकता होगी। वर्तमान में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए ज्यादातर विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों पर निर्भर हैं। इंटरनेट पर भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित व्यापक सामग्री उपलब्ध हैं, लेकिन आकर्षण कोचिंग संस्थान ही हैं। यदि स्कूली बच्चों में ही बच्चों में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति रुचि पैदा कर दी जाए तो उनके समक्ष महंगे कोचिंग संस्थानों में नामांकन लेने की मजबूरी नहीं रहेगी। स्वाध्याय से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने नौवीं से बारहवीं कक्षा के बच्चों को जेईई और नीट के साथ एनडीए, ओलंपियाड, एसएससी और रेलवे से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सामान्य ज्ञान को बेहतर करने के लिए हर महीने पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्य पाठ्यक्रम के साथ इस तरह की शिक्षा निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की नींव मजबूत करेगी। सरकारी विद्यालयों से मैट्रिक और इंटर करने वाले विद्यार्थी भी स्वयं को प्रतियोगी माहौल में खड़ा कर सकेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि शिक्षा परियोजना परिषद का प्रयास सफल साबित हो सकता है। इससे पाठ्य सामग्री एवं शैक्षिक संसाधनों से वंचित बड़ी संख्या में छात्रों को सुविधा मिलेगी।

> सामान्य पाठ्यक्रम के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की मेधा को मिलेगी सही दिशा

और बढ़ी वायु सैन्य शक्ति की महत्ता

अजय कुमार

आज हवाई सैन्य शक्ति टकराव को व्यापक रूप से बढ़ाए बिना दूर बैठे ही दुश्मन को घर में घुसाकर दंडित करने में बहुत उपयोगी साबित हो रही है

अवधेश राजपूत

आपरेशन सिंदूर ने भारत की उन क्षमताओं को साबित किया कि पाकिस्तान की धरती पर कदम रखे बिना भी उसके भीतरी इलाकों में स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। अमेरिका और इजरायल ने भी ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हवाई हमलों के जरिये ऐसी ही क्षमताएं दिखाईं। तुर्किये से लेकर रूस जैसे देश अपनी वायु सैन्य शक्ति विशेषकर ड्रोन जैसी तकनीक पर भरोसा करते हैं। वायु और अंतरिक्ष में किसी देश की क्षमताएं ही उसकी सामरिक शक्ति को निर्धारित कर रही हैं, क्योंकि इसके जरिये सुदूरवर्ती जगह से भी पूरी सटीकता एवं तत्परता से हमला कर दुश्मन को क्षति पहुंचाई जा सकती है। अतीत में युद्ध संसाधनों की दृष्टि से जमीन कब्जाने के लिए लड़े जाते थे, जिसमें जमीन पर सक्रिय सैन्य बलों के लिए वायु शक्ति सहायक की भूमिका निभाती थी। जमीन कब्जाने के साथ और जटिलताएं जुड़ी होती हैं, जैसे उस पर काबिज होने के बाद वहां गवर्नेंस भी कई बार बोझ बन जाती है। स्थानीय लोगों के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ता है जो अक्सर गुरिल्ला युद्ध का रूप ले लेता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। अपने उपनिवेशों से ब्रिटेन का निकलना, वियतनाम, अफगान और अफगानिस्तान से अमेरिका का पलायन और अफगानिस्तान से सोवियत संघ का पीछे हटना यही साबित करता है कि क्षेत्रीय कब्जे में गवर्नेंस का अंतर्निहित बोझ छिपा होता है। यही कारण है कि आधुनिक समर नीति में युद्धों का स्वरूप बदल गया है।

समय के साथ वायु सैन्य शक्ति को लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण बदला है। एक समय इसे उकसाने वाला कदम समझा जाता है, लेकिन अब इसे सटीक प्रहार वाली नियंत्रित कार्रवाई के रूप में मान्यता मिल रही है। भारत के बालाकोट और आपरेशन सिंदूर जैसे अभियान से लेकर ईरान पर अमेरिका-इजरायल की बमबारी यही साबित करती है कि वायु सैन्य शक्ति टकराव को व्यापक रूप से बढ़ाए बिना ही दुश्मन को घर में घुसकर दंडित करने में उपयोगी साबित होती है। चूंकि ऐसे हमले मुख्य रूप से खुफिया जानकारी पर आधारित चिह्नित आतंकी या सैन्य इलाकों को निशाना बनाकर किए जाते हैं तो इसमें आम जन हानि की आशंका भी घट जाती है। युद्ध का बुनियादी सिद्धांत ही यही है कि दुश्मन आपके हमले से चौंक जाए। वायु सैन्य शक्ति चौंकाने वाले इस पहलू को सुनिश्चित करती है। यह जितनी गति, तत्परता और सटीकता से लक्ष्य को साधती है, उसकी किसी अन्य पारंपरिक सैन्य शक्ति से तुलना संभव नहीं। इसके जरिये दुश्मन के कमांड सेंटर, आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे को चोट पहुंचाकर उसकी कमर तोड़ना संभव है।

वायु सैन्य शक्ति भी समय के साथ बहुत उन्नत होती गई है। पूर्व में मिग-21 जैसे विमान बेस से केवल कुछ सैकड़ों किमी दूर तक ही संचालित हो सकते थे। आज लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाले बमवर्षक, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों के साथ ही हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा ने हजारों किमी दूर सुदूरवर्ती इलाकों तक मार करने की क्षमता दिलाई है और वह भी दुश्मन के वायु क्षेत्र में प्रवेश किए बिना। मिसाइलों तो 1,000 किमी से भी दूर तक निशाना लगा सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें तो कम समय में ही काम निपटा सकती हैं। बी-52 और राफेल जैसे विमान हवा में ही ईंधन भरकर घंटों तक उड़ते हुए महाद्वीपों की सीमा को पार कर सकते हैं। एमक्यू-9 रीपर जैसे ड्रोन दिन भर से अधिक तक अपने लक्ष्य के ऊपर मंडरा सकते हैं।

निःसंदेह भारत ने अपनी वायु सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी की है और यह क्रम निरंतर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमें चीन को लेकर अपनी सतर्कता भी बढ़ानी होगी, जिसने अपनी समरिक शक्ति को बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। चीनी वायु सेना के पास 200 से अधिक जे-20 स्टील्थ फाइटर्स हैं और पिछले 15 वर्षों में उसने आधुनिक लड़ाकू विमानों के अपने बेड़े को तीन गुना तक बढ़ाया है। एच-6के बमवर्षक के साथ लंबी दूरी की उसकी मारक क्षमताएं बढ़ी हैं तो बाई-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिये सैनिकों और रसद सामग्री को तेजी से कहीं भी पहुंचाने की उसकी क्षमता में इजाफा हुआ है। चीन ने लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली पीएल-15 जैसी मिसाइल विकसित की है और उसके उन्नत संस्करणों को तैयार करने में भी लगा हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी वह भारी दांव लगा रहा है। चीन के मिसाइल लांचर भी 2000 के बाद दोगुने से अधिक हो गए हैं। उसका बायडू सैटेलाइट सिस्टम सामरिक मोर्चे को लक्षित करने और नेविगेशन से लेकर संचार सुविधाओं में सहयोग करता है। पाकिस्तान के साथ चीन की नजदीकियों को देखते हुए भारत की चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। इसलिए भारत को न केवल अपनी मौजूदा रक्षा प्रणालियों, बल्कि आधुनिक क्षमताओं के विकास को लेकर भी तत्परता का परिचय देना होगा। इसमें एएमसीए, एलसीए, एमके-टू, लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, एमएएलई और एचएएलई ड्रोन और हवा में ईंधन भरने की आत्मघातिक तकनीकों को प्राथमिकता में रखना होगा। एडवांस रडार और सेंसर सुइट्स, इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम्स व पूर्णतया सुरक्षित एवं एआइ-संचालित कमांड एवं कंट्रोल नेटवर्क विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अंतरिक्ष मोर्चे पर भारत को सैटेलाइट निगरानी, नाविक, संचार, अर्ली-वार्निंग और एंटी-सैटेलाइट क्षमताएं विकसित करनी होंगी। वायु रक्षा प्रणालियों का एकीकरण और विभिन्न सैन्य बलों में उनके उपयोग को सुगम एवं लचीला बनाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए स्वदेशी शोध एवं विकास में निरंतर निवेश बढ़ाना होगा। सार्वजनिक-निजी भागीदारी भी मजबूत बनाई जाए। खरीद प्रक्रिया को तीव्र किया जाए। वायु और अंतरिक्ष क्षमताएं ही अब संहारक एवं निवारक क्षमताओं को निर्धारित कर रही हैं तो भारत प्राथमिकता के आधार पर अपने औद्योगिक आधार को सक्रिय एवं सशक्त करते हुए ऐसी क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करे।

(लेखक सीव लांच सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व रक्षा सचिव हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

response@jagran.com

आखिर जोहरान से हमारा क्या लेना-देना!

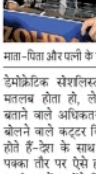

राजीव सचान

भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को हर भारतवंशी की सफलता पर इतराना छोड़ देना चाहिए

माता-पिता और पत्नी के साथ जोहरान ममदानी। प्रेट्र

हो सकता है भारतवंशी जोहरान ममदानी न्यूयार्क शहर के मेयर बन जएं। इसकी प्रबल संभावना इसलिए है, क्योंकि वे अप्रत्याशित रूप से मेयर का प्राइमरी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने प्राइमरी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी से एंड्रयू कुओमो को हराया था। उनके न्यूयार्क के मेयर बनने-न बनने के बारे में नवंबर में पता चलेगा। उनकी जीत की संभावना को लेकर अमेरिका से लेकर भारत तक हलचल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी जीत की संभावना को एक खतरे के रूप में देखा है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर डेमोक्रेट पार्टी के प्रत्याशी जोहरान ममदानी को सौ प्रतिशत कम्युनिस्ट बताते हुए कहा, 'मैं इस बेवकूफ कम्युनिस्ट को न्यूयार्क शहर बर्बाद नहीं करने दूंगा।' इससे पहले भी ट्रंप ने ममदानी को चेताया था कि यदि उन्होंने न्यूयार्क में इमिग्रेशन और कस्टम्स इंफोर्समेंट के छापों में अड़ंगा डाला तो उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। ट्रंप की जवाब देते हुए ममदानी ने कहा था कि राष्ट्रपति के बयान लोकतंत्र पर हमला हैं।

जोहरान भारत में जन्मीं जानी-मानी फिल्म निर्माता-निर्देशक मीरा नायर और युगांडा के गुजराती मूल के प्रोफेसर महमूद ममदानी के पुत्र हैं। महमूद का जन्म मुंबई में हुआ था। पंजाबी हिंदू मीरा नायर का जन्म और शिक्षा-दीक्षा भारत में हुई। पद्मश्री से सम्मानित मीरा की चर्चित फिल्में हैं-मानसून वेडिंग, सलाम बांबे। यदि 33 साल के जोहरान ममदानी मेयर का चुनाव जीतते हैं तो वे न्यूयार्क के पहले मुस्लिम एवं भारतवंशी मेयर होंगे। उन्होंने तमाम लोकलुभावन वादे किए हैं। उनका एक वादा यह भी है कि राजस्व बढ़ाने के लिए वे अमीरों पर टैक्स बढ़ाएंगे। जोहरान न्यूयार्क की प्रतीय विधायिका के सदस्य हैं। उनकी पत्नी सीरियाई मूल की रमा दुवाजी हैं। जोहरान का जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ। वे सात वर्ष की उम्र में माता-पिता के साथ न्यूयार्क चले आए। जोहरान के एक बयान पर बकील एवं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि जब वे अपना मुंह खोलते हैं तो पाकिस्तान की पीआर टीम छुट्टी ले लेती है। भाभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि वे भारतीय की तुलना में पाकिस्तानी ज्यादा लगते हैं। जोहरान खुद को डेमोक्रेटिक सेशलिस्ट मानते हैं। इसका जो भी मतलब होता हो, लेकिन खुद को ऐसा कहने-बताने वाले अधिकतर लोग इस्लामिस्ट की भाषा बोलने वाले कट्टर किस्म के वामपंथी ही अधिक होते हैं-देश के साथ दुनिया में भी। जोहरान तो पक्का तौर पर ऐसे ही हैं। एक समय एक पोस्ट (एबीट) में उन्होंने लिखा था कि हो न हो, यमन मूल का अमेरिकी आतंकी अनवर अल-अवलाकी को एकबीआइ की तरफ से की गई निगरानी के कारण ही उसका रुख अल-कायदा की ओर हुआ होगा। इससे अधिक मूर्खतापूर्ण और आतंकी का बचाव करने एवं उससे हमदर्दी जताने वाली पोस्ट और कोई नहीं हो सकती, लेकिन दुनिया में ऐसे कथित प्रगतिशील लोगों की कमी नहीं, जो खूंखार आतंकी का भी बेशर्मी से बचाव करते हैं। इसके बाद भी वे लिबरल-सेक्युलर कहलाते हैं और इसके प्रमाणपत्र भी बांटते हैं कि कौन सेक्युलर है और कौन सांप्रदायिक?

ज्यादातर लिबरल और सेक्युलर अनुदारवादी और संप्रदायिक किस्म के नकली लोग होते हैं, लेकिन बौद्धिक जगत में उनकी उनकी ही हनक है-भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप में भी। अवलाकी का बचाव करने वाली जोहरान की पोस्ट की 9/11 हमलों के पीड़ितों के परिवारों और अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने निंदा की थी। एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, 2007 से 2011 के बीच अमेरिका में आतंकवाद के जितने भी मामले दर्ज हुए, उनमें 20 से प्रतिशत से अधिक में अल-अवलाकी समर्थकों का हाथ था।

जोहरान बड़े ही चतुर नेता हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रंप समर्थक और विशेष रूप से श्वेतपंथी अतिवादी किस्म के लोग उन्हें निशाना बनाएं और इसके नतीजे में न्यूयार्क में रह रहे मुसलमानों समेत भारतीय एवं अन्य देशों के लोग उनके समर्थन में खड़े हों, जोहरान ने खाना खाते एक फोटो पोस्ट की। इस फोटो से ऐसा लगा कि वह ऐसे भारतवंशी हैं, जो अंगुलियों से खाना खाना पसंद करते हैं। उन्होंने इसी तरह के कुछ और भी उपक्रम किए हैं। वे मोदी के कट्टर विरोधी हैं। उनका एक पुराना बयान यह कहता है कि मोदी के मुख्यमंत्री रहते समय गुजरात में मुसलमानों पर इतना अत्याचार हुआ कि लोगों ने यह मानना ही छोड़ दिया कि गुजरात में मुसलमान रहते हैं। पता नहीं वे न्यूयार्क के मेयर बनेंगे या नहीं, लेकिन ऐसे भारतवंशियों के प्रति भारतीयों का उत्साहित होना लाजमी ही है। भारतवंशी दुनिया में कहीं भी जब किसी उच्च पद पर पहुंचते हैं तो भारतीयों का ध्यान उनकी ओर जाता ही है। यह स्वाभाविक है, लेकिन यह मान लेना सही नहीं कि वे भारत के हित की चिंता करेंगे। ऐसा बहुत कम होता है। इसका एक उदाहरण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के हित में कुछ भी नहीं किया-न नीरव मोदी के खिलाफ कोई कदम उठाया और न ही ब्रिटेन में उत्पात मचा रहे खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की। देश-विदेश के भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को हर भारतवंशी की सफलता पर बेवजह इतराना छोड़ देना चाहिए।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वैराग्य का अर्थ

मानव मन चंचल है। मन का संसार के विषयों में भटकना और आकर्षित होते रहना ही शायद हमारे मानवीय गुणों और सीमाओं का परिचायक है। मन विषयों की कल्पना का संसार बुनता है, चित्त उस ओर आकर्षित होता है और इंद्रियां उनका अनुभव करना चाहती हैं। पातंजलि योगसूत्र के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, परंतु क्या यही वैराग्य है? सिर्फ इंद्रियों और चित्त पर लगाम लगाना ही पर्याप्त है? यदि मूलरूप से देखें तो इसका उत्तर 'हां' हो सकता है, परंतु दार्शनिक दृष्टि से समझ आता है कि वैराग्य इससे आगे भी बहुत कुछ है।

संसार तमाम महापुरुषों और योगियों के योगदान से चैतन्य है। कुछ लोग संसार के लाभ के लिए ही संसार की चमक से दूर उस परम तत्व की खोज के मार्ग में अग्रसर रहते हैं, तो कुछ संसार में रहकर ही जनमानस को जगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जो संसारी विषयों को त्यागकर ब्रह्म में लीन है वो तो विरक्त है ही, परंतु जो संसार में रहकर संसार के रहस्य को समझने का प्रयास करे और उस परम सत्य की खोज करे वो भी विरक्त ही है। कारण यही कि बिना ईश्वर इच्छा के उस परमतत्व की खोज का विचार भी किसी के मन में नहीं आ सकता। कौपीन पंचकम् में जब आदि शंकराचार्य कहते हैं, 'कौपीन वन्तः खलु भाग्यवन्तः' तब उनका अभिप्राय सिर्फ कौपीन से नहीं, बल्कि वैराग्य से होता है। वे कहते हैं कि धन्य हैं वे जिन्हें ईश्वर ने वैराग्य दिया है।

इसलिए जो वैराग्य भीतर से जन्म ले, जो व्यक्ति को आराधाना बनाए और जो पूर्णतता का अनुभव कराए, वही वास्तविक वैराग्य है। अन्यथा किसी के प्रभाव से न तो वैराग्य मिल सकता है और न संसार। इसलिए कहा जा सकता है कि जो संसार के साथ या संसार के बिना भी ब्रह्म में लीन है, वही विरक्त है। वही जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने वाला साधक है।

आदित्य नारायण अवस्थी

जीवन पर भारी पड़ती अनदेखी

मोनिका शर्मा

कुत्ते और कुछ अन्य जानवरों के काटने पर समय रहते लेना चाहिए एंटीरेबीज का इंजेक्शन

हाल ही में हुई एक 22 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी बृजेश की मृत्यु रेबीज की बीमारी को लेकर चेतावनी देने वाला दुखद वाकया है। छोटी सी अनदेखी के चलते तड़प-तड़पकर इस युवा खिलाड़ी की मौत हुई है। यह पीड़ादायी घटना आमजन को सजगता बरतने के साथ ही सबक देने वाली भी है। ध्यातव्य है कि निकट भविष्य में ओलिंपिक में हिस्सा लेने जाने वाले कबड्डी खिलाड़ी ने बीते दिनों एक जगह नाले में कुत्ते के एक पिल्ले को देखा जो वहां से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस खिलाड़ी ने उस पिल्ले को बाहर निकाला, लेकिन उसी दौरान उस पिल्ले ने खिलाड़ी के हाथ पर दंत मार दिया था। मामूली खरोंच समझकर बृजेश ने घाव पर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ समय बाद इस खिलाड़ी का हाथ सुन्न हो गया और शरीर में अजीब सी छटपटाहट महसूस होने लगी। इन शिकायतों के बाद अस्पताल पहुंचे बृजेश ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। एंटी-रेबीज टीका नहीं लगवाने और जानकारी के अभाव में समय रहते उपचार नहीं मिलने के कारण रेबीज वायरस के संक्रमण ने उनकी जान ले ली।

दरअसल, कुत्ते के काटने के बाद एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना आवश्यक है। बच्चे हों या बड़े, चिकित्सकीय सलाह और एंटी-रेबीज टीका लगवाना पहली प्राथमिकता होना चाहिए। देखने में आता है कि कुत्ते के काटने के छोटे-मोटे घाव को कई बार गंभीरता से नहीं लिया जाता है। कुछ दिनों बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने पर इस ओर ध्यान दिया जाता है। तब तक रेबीज का संक्रमण घातक स्थिति में पहुंच जाता है। इस जानलेवा व्याधि के लक्षण दिखने तक मरीज का जीवन संकट में पड़ चुका होता है। कुत्ते ही नहीं, दूसरे किसी जानवर के काटने को भी सहजता से लेना जीवन पर भारी पड़ सकता है। ऐसे मामलों में चिकित्सकीय सलाह लेने में देरी नहीं होनी चाहिए। हालिया दिनों में सामने आए कई मामले बताते हैं कि कुत्ते के काटने के बाद अविलंब चिकित्सा सहायता न लेना व्यक्ति की जिंदगी ही लील गया। ध्यान रहे कि रेबीज की रोकथाम रेबीज के टीके के माध्यम से ही की जा सकती है।

भारत ही नहीं, दुनियाभर में रेबीज लोगों का जीवन छीनने वाली बीमारी बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, रेबीज से हर साल दुनियाभर में 26 हजार से 59 हजार लोगों का जीवन छिन जाता है। इनमें 95 प्रतिशत अधिक मामले एशिया और अफ्रीका में होते हैं। ऐसे में इस जानलेवा संक्रमण को लेकर सजगता जरूरी है। ध्यातव्य यह भी है कि कुत्ते के अलावा बिल्ली, बंदर, चमगादड़, चूहे, गिलहरी, नेवला, लोमड़ी आदि के काटने से भी रेबीज फैलने की आशंका होती है। एक राज्य स्तरीय खिलाड़ी के साथ हुआ जानलेवा हादसा इस भयावह व्याधि को लेकर नई बहस छेड़ने वाला तो है ही, जागरूकता के मोर्चे पर आमजन को चेताने वाला भी है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

उपयोगी पहल का अनावश्यक विरोध

'केरल से कुछ सीखें अन्य सरकारें' शीर्षक से प्रकाशित आरिफ हुसैन का आलेख पढ़ा। लेखक के विचार उचित हो हैं कि कोई एरोबिक जैसी कवायद भला कैसे अनुपयोगी सिद्ध हो सकती है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि बच्चे या किशोर कसरत जैसी किसी गतिविधि को लेकर उत्साहित नहीं रहते। आधुनिक जीवनशैली और बिगड़े खानपान के साथ ही अभिभावकों की अपेक्षाकृत व्यस्तता एवं अनदेखी से जब बच्चे एवं किशोरों के भटकने की आशंका कहीं अधिक बढ़ गई है, तब जुंबा जैसी किसी गतिविधि का तो स्वागत किया जाना चाहिए जिसमें बच्चे एवं किशोर खुशी-खुशी शामिल होना चाहें। ऐसी किसी पहल का विरोध कुछ और नहीं, बल्कि पिछड़ेपन और दकियानूसी होने की ही निशानी है। यह एक उपयोगी पहल का अनावश्यक विरोध ही है। जुंबा डांस को स्कूली गतिविधियों में शामिल करना न केवल स्वास्थ्य की दिशा में केरल सरकार का एक रचनात्मक प्रयास है, बल्कि यह नशे के खिलाफ एक सशक्त सामाजिक संदेश भी है। यह माडल अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय साबित हो सकता है। इसलिए सुझाव है कि देश के अन्य राज्य भी इसे शीघ्र लागू करें, ताकि बच्चों के हित में एक अहम सुधार आकार ले सके।

डा. प्रदीपकुमार संघवी, शिवाजिवृ, झाबुआ (मप्र)

भ्रष्टाचार की स्वतंत्र जांच

मंगलवार को संपादकीय पेज पर प्रकाशित अग्रलेख 'फर्जी लाभार्थी' में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पात्रता जांचने के लिए और दस्तावेज प्रमाणीकरण हेतु केवाईसी की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। गरीबों, वंचितों और पिछड़ों के उत्थान हेतु किसी भी सरकारी योजना का अनुचित लाभ उठाकर फर्जी लाभार्थी न केवल दूसरों के हक पर डाका डाल रहे हैं, बल्कि योजना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति में भी बाधक बन रहे हैं। शासन की योजनाओं का लाभ केवल और केवल उचित, पात्र और जरूरतमंदों को मिले, इसके लिए केवाईसी अनिवार्य किया जाना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना इसलिए अस्तित्व में आई, ताकि सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन, सरकारी सहायता आदि का लाभ सीधे तौर पर पात्र व्यक्ति को ही मिले। यह सही है कि सरकार की अनेक योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें यह कटु सत्य भी स्वीकारना होगा कि जब तक योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा, वे अपने मूल उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगी। भ्रष्टाचार अब भी देश के सम्मुख एक ज्वलंत समस्या के रूप में कायम है, सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठाने या देने के लिए रिश्वतखोरी, मिलीभगत और फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर होता है। अतः समय-समय पर योजना की समीक्षा और निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था की महती आवश्यकता को नकारा नहीं जाना चाहिए। स्वतंत्र जांच एजेंसी इसलिए जरूरी है, क्योंकि ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जिनसे जुड़े भ्रष्टाचार में नेता, मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी सभी संलिप्त पाए गए हैं। शासन-प्रशासन जब किसी जनकल्याणकारी योजना के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर में सुधार की कोशिश करती है तो उसका यह दायित्व भी है कि वह यह भी जांच करे कि वास्तव में लक्षित वर्ग ही लाभार्थी है या नहीं? समाज या राष्ट्र के नागरिकों द्वारा भ्रष्टाचार को सामान्य चलन की तरह स्वीकार्य करने की मानसिकता को बदलना होगा। भ्रष्टाचारियों को धरपकड़ कर उनसे वसूली की जाए और कड़ी सजा दी जाए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है, ताकि भविष्य में फिर कोई सरकारी योजना में सेंध लगाने की कोशिश करने से पहले हजार बार सोचे। भ्रष्टाचार दोहरी चोट दे रहा है, एक तरफ तो वंचित लोग तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी सुविधाओं से वंचित ही रह रहे हैं तो दूसरी तरफ अपात्र, फर्जी पात्र बनकर कई लोग सरकार को चूना लगा रहे हैं। चाहे राज्य हो या केंद्र सरकार, भ्रष्टाचार को दूर करना और उसे पूर्णतया समाप्त करना उनका कर्तव्य है, लेकिन समस्या यह भी है कि वे स्वयं भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं और स्वयं इसके लिए जिम्मेदार भी। जब इलाज करने वाला स्वयं ही रोगी हो तो पहले उसका इलाज आवश्यक हो जाता है।

मोहित सोनी, कुर्सी, धार, मध्य प्रदेश

उस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समाचार सामग्री के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

48 हजार थी महिला पीएचडी शोधार्थियों की संख्या समूचे देश में वर्ष 2014-15 के दौरान, जबकि वर्ष 2021-22 में यह संख्याबढ़कर 99 हजार तक पहुंच गई।

आजकल

उच्च शिक्षा में छात्राओं की बढ़ती भागीदारी

महज 21 वर्ष की उम्र में जाह्नवी पंवार आइआइटी दिल्ली में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश लेकर देश की सबसे कम उम्र की पीएचडी स्कालर बन गई हैं। आम तौर पर इस उम्र में युवा अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं। ऐसे में जाह्नवी की सफलता इस बात का भी प्रमाण है कि बेटियां अब न केवल शिक्षा में बराबरी कर रही हैं, बल्कि आगे बढ़कर नेतृत्व भी कर रही हैं। यह केवल एक असाधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि देश में महिलाओं की उच्च शिक्षा में बढ़ती भागीदारी का जीवंत उदाहरण भी है। इससे इस प्रकार की अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी

सुधीर कुमार
शोधार्थी, बीएचयू, वाराणसी

प्रतीकात्मक

हाल के वर्षों में भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। आनलाइन शिक्षण और रोजगार समाधान प्रदाता कंपनी 'टीमलीज एडटेक' द्वारा बीते दिनों जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में देश के विश्वविद्यालयों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नामांकन में कई गुना अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस समयावधि के दौरान जहां पुरुषों के नामांकन में महज 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं महिलाओं में यह वृद्धि 26 प्रतिशत तक देखी गई। खास बात यह है कि यह वृद्धि न केवल विषयगत पाठ्यक्रमों में दिखाई दी है, बल्कि कार्य एकीकृत कार्यक्रमों (प्रशिक्षण आधारित कोर्स) में भी महिला आवेदकों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन पाठ्यक्रमों में जहां पुरुषों के नामांकन में 66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं महिलाओं में यह वृद्धि 124 प्रतिशत की तक रही।

ये आंकड़े निश्चित रूप से भारत में उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के संबंध में उत्साहजनक तस्वीर पेश करते हैं। महिलाओं का उच्च शिक्षा में प्रवेश महज आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी संकेतक है कि महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो रही है और समाज की रूढ़िगत मानसिकता में बदलाव आ रहा है। यह लैंगिक भेदभाव और शोषण से मुक्त तथा आत्मनिर्भर समाज की स्थापना की राहें खोल रहा है।

उच्च शिक्षा के भी कोर्स में बढ़ा दबदबा : उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की पुष्टि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट भी करती है। इसके अनुसार, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध स्तर के पाठ्यक्रमों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक देखने को मिल रही है। वर्ष 2022 में स्नातक स्तर पर बैचलर आफ आर्ट्स (बीए) कोर्स में प्रत्येक 100 पुरुषों पर नामांकित महिलाओं की संख्या 113 दर्ज की गई, जबकि बैचलर आफ साइंस (बीएससी), बैचलर आफ आर्ट्स (आनर्स) और बी.एड. (बैचलर आफ एजुकेशन) कोर्स में यह क्रमशः 108, 124 और 176 दर्ज किया गया, जो उच्च शिक्षा में महिलाओं की विशेष रुचि और भागीदारी को दर्शाता है। एमबीबीएस जैसी मेडिकल शिक्षा में भी महिलाओं का दबदबा बना हुआ है, जहां 57.6 प्रतिशत महिलाओं के बरक्स पुरुषों की हिस्सेदारी 42.4 प्रतिशत देखी गई है। जाहिर है, पारंपरिक रूप से चुनौतीपूर्ण मानी जाने वाली चिकित्सा के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी सशक्त रूप से बढ़ रही हैं।

हालांकि महिलाओं की सहभागिता केवल स्नातक स्तर पर ही नहीं बढ़ी है, बल्कि स्नातकोत्तर और पीएचडी जैसी उच्च डिग्री कोर्स में भी परिलक्षित होती है। यह रिपोर्ट बताती है कि एम.ए. में प्रत्येक 100 पुरुषों पर 170, एम.एससी. में 157 और एम.एड. में आश्चर्यजनक रूप से 202 महिलाएं नामांकित हैं। शोध के क्षेत्र में भी देखें तो महिला शोधार्थियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। वर्ष 2014-15 में जहां देशभर में महिला पीएचडी शोधार्थियों की संख्या 48 हजार थी, वहीं 2021-22 में यह संख्या बढ़कर 99 हजार हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा के सभी चरणों में महिलाओं की उपस्थिति विशेष रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यह एक बड़े सामाजिक बदलाव की ओर इशारा करती है। महिलाएं पारंपरिक दायरों से बाहर निकलकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पहुंच रही हैं और अपने सपने पूरे करने में जुटी हैं। पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा कर पाना शायद कुछ समय पहले तक इतना भी सहज नहीं था, किंतु महिलाओं द्वारा उपलब्ध अवसरों का सक्रिय रूप से उपयोग किए जाने के कारण यह मार्ग उनके लिए सुगम होता गया। यह बदलाव पढ़ाई को लेकर घरों में होने वाले लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में मिल का पत्थर साबित हो सकती है।

महिला शिक्षा के प्रति दूर होता पूर्वाग्रह : महिला शिक्षा से जुड़े आंकड़े किसी भी देश के समग्र विकास के प्रमुख संकेतक होते हैं। महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में शिक्षा के महत्व को नजरअंदाज करके नहीं देखा जा सकता है। निस्संदेह, उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी अर्थव्यवस्था को विस्तार देने और समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने की दिशा में एक प्रभावशाली आयाम है। महिला शिक्षा समग्र और दीर्घकालिक विकास की कुंजी मानी जाती है। इसमें तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तक समान और बढ़ती पहुंच शामिल है। युवाओं के प्रेरणास्तंभ स्वामी विवेकानंद का भी मानना था कि महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें अपने भाग्य का फैसला करने देना आवश्यक है। उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी बताती है कि अब लड़कियों की प्राथमिकता विवाह नहीं है, बल्कि शिक्षित और आत्मनिर्भर होना उसकी पहली पसंद बन गई है। यही वजह है कि जहां लड़कियों को पहले दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के बाद या अधिकतम बी.एड. की डिग्री दिलाकर ब्याह दिया जाता था, वहीं अब लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के प्रति अभिभावक संजीदा हो रहे हैं। वे भी यह अच्छी तरह समझने लगे हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त किए बिना बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें श्रम बाजार के लिए तैयार कर पाना संभव नहीं है।

भारतीय समाज में एक समय ऐसा भी था, जब अभिभावक अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से भी कतराते थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि लड़कियां घर की चौखट को लांघ कर न केवल स्कूल, बल्कि विश्वविद्यालय की परिधि में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा रही हैं। यह बदलाव नारी शक्ति की दिशा में एक बड़ी छलांग है। महिलाओं का पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे पीढ़ियों को सुधारा जा सकता है। महिलाओं को ज्यादा पढ़ाना उनकी रोजगार के अवसरों से जोड़ने में सहयोग करता है, जिससे उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सकता है। एक समय ऐसा था, जब महिलाओं का धन अर्जित करना आवश्यक नहीं समझा जाता था, लेकिन पुरुषों पर आत्यधिक आर्थिक निर्भरता के परिणामस्वरूप कई बार उनकी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता सीमित हो गई।

अर्थव्यवस्था में बढ़ती हिस्सेदारी : महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने से अधिक समृद्ध और न्यायसंगत समाज की स्थापना की जा सकती है। 'आधी आबादी' को शिक्षित करने से वे भी अर्थव्यवस्था में समान रूप से अपनी हिस्सेदारी निभा सकेंगी, जिससे देश को समग्र विकास की दिशा में मजबूती मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने से महिलाओं को श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में सहायता मिली है। इससे श्रम बल में व्याप्त लैंगिक अंतर को पाटा जा सकता है और लैंगिक समानता की वैचारिकी को समग्र रूप में स्थापित किया जा सकता है। जब एक महिला पढ़ती है, तो वह आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भेदभावरहित परिवार और समाज की राहें खोलने का काम करती हैं। अशिक्षा के कारण भेदभाव झेलने वाली महिलाएं जब शिक्षित होती हैं, तो वे समाज में समानता और न्याय के व्यवहार को अपनाती हैं। इसलिए उच्च शिक्षा में महिलाओं की सतत भागीदारी को यथावत कायम रखना आवश्यक है। जाहिर है, इसमें सरकार और समाज का सहयोग भी अनिवार्य है।

शिक्षा प्राप्ति में महिलाओं के समक्ष चुनौतियां

उच्च शिक्षा में महिलाओं के प्रवेश के वर्तमान आंकड़े उत्साहित जरूर करते हैं, लेकिन तस्वीर के दूसरे पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः सच्चाई यह है कि देशभर में आज भी लाखों लड़कियों के लिए विद्यालय और विश्वविद्यालय की चहारदीवारी तक पहुंचना आसान नहीं है। लड़कियां विश्वविद्यालय तक पहुंचें, इसके लिए सबसे पहले उनका स्कूल तक पहुंचना सुनिश्चित करना होगा। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान से बालिका शिक्षा के प्रति धारणाएं तो बदली हैं, लेकिन वस्तुस्थिति पूरी तरह तभी बदलेगी जब बदलाव मानसिक स्तर पर और समग्रता से दिखाई देंगे। संयुक्त राष्ट्र की संस्थान यूनिसेफ (यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड) का अनुमान है कि आज भी दुनियाभर में 12.2 करोड़ लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। अतः सबसे पहले प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में लैंगिक समानता लानी होगी, तभी जाकर उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच हो पाएगी। गरीबी, हिंसा, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लाखों लड़कियां प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित हैं। इस दिशा में सार्थक प्रगति के लिए केवल नीतिगत प्रयास ही नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में भी व्यापक परिवर्तन आवश्यक है। जब समाज बेटियों की शिक्षा को अधिकार नहीं, बल्कि अनिवार्यता मानेगा, तभी वे बिना किसी बाधा के स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगी।

बहरहाल, उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी उत्साहजनक तो है, लेकिन देश में स्कूली शिक्षा को भी उपयोगी बनाने पर ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं को उनकी क्षमता और कौशल के हिसाब से रोजगार के अवसर से भी जोड़ा जाए। इससे और भी महिलाएं आकर्षित होंगी। साथ ही, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ शैक्षिक और कार्यस्थल संबंधी दायित्वों में संतुलन स्थापित करने के लिए परिजनों का सहयोग अपेक्षित है। कई अध्ययन बताते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण तकरीबन 83 प्रतिशत तक महिलाएं अपने करियर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने के लिए संघर्ष करती हैं, अक्सर स्वयं की घर और कार्यस्थल के बीच उलझा हुआ पाती हैं। ऐसे में यह परिदृश्य बदलना भी जरूरी है, ताकि वे भी अपने सपने पूरी कर सकें।

(सुधीर कुमार)

खरी-खरी

'मी टू' का मेल वर्जन

पिछले कुछ वर्षों में अचानक जिस तरह 'मी टू' शब्द उभर कर आया है, इस पर कभी कभी सोचती हूं कि यदि इसका 'मेल वर्जन' आए तो क्या होगा? अभी हाल ही में मुंबई की एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ यौन शोषण के आरोप में पकड़ी गई। हां, कुछ पुरुष गलत होते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक अपनी कुंठाएं निकालते हैं, ऐसे पुरुषों का विरोध, उनकी कुटाई जरूरी है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि महिलाएं संत होती हैं। मैंने मीडिया क्षेत्र में काम किया है और अब साहित्य में कर रही हूं। यहां पर एक चीज देखने को मिली, वह यह कि यहां जबरदस्ती नहीं होती, हां आपसी सहमति से जरूर संबंध बनते हैं, वह भी फायदे के लिए।

आत्मनिर्भर स्त्री के पास हमेशा च्वाइस होती है शर्टकेट लेकर आगे जाए या लात मार कर पीछे आए। लेकिन होता क्या है? जब तक इन महत्वाकांक्षी लड़कियों और स्त्रियों की हिम्मत पूरी होती रहती है, ये आराम से बिना मेहनत तरक्की का आनंद लेती हैं और जिस दिन इनके मन की नहीं होती उसी दिन 'मी टू' शुरू हो जाता है। अरे, कुछ गलत था तो उसी समय कुटाई करती, शोर मचाती। कुछ ही मजबूर होती हैं, सब नहीं।

हां, कुछ पुरुष बहुत खराब होते हैं, इसका अनुभव हम लड़कियों को बचपन से ही हो जाता है, इसलिए हम सतैव चौकन्ने रहते हैं, परंतु अपने फायदे के लिए पुरुषों का सहारा लेने वालियों की बात कौन करेगा? पुरुष की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन वही पुरुष अनेक स्त्रियों की इज्जत संभाले बैठे हैं। जिस दिन पुरुषों ने अपना मुंह खोला, उस दिन कई बड़ी कवियत्री, साहित्यकार, पत्रकार, हीरोइन, बड़े पद पर बैठी स्त्रियों के मुखौटे उतर जाएंगे।

इन्हीं स्त्रियों की वजह से अपनी प्रतिभा और मेहनत से आगे बढ़ने वाली महिलाओं के आगे बढ़ने के रास्ते और कठिन हो जाते हैं, जाने कितने ही सपने आंखों में ही दम तोड़ देते हैं। शायद बहुत जल्द पुरुषों के मी टू का समय भी आएगा। आखिर बात तो बराबरी की है : केवल स्त्री नहीं, पुरुष का भी शोषण होता है। मर्द तरकी होते हैं, लेकिन ऐसी स्त्रियों की क्या कहेंगे?

(अर्चना चतुर्वेदी की फेसबुक वाल से संपादित अंश, साभार)

X पोस्ट

दलाई लामा को भारत रत्न दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। समय और परिस्थितियों को देखते हुए भी ऐसा किया जाना बहुत शानदार होगा।
आदित्य राज कौल@AdityaRajKaul

भारत के यूट्यूबर ऐसा क्या करते है कि पाकिस्तान में उन पर बैन नहीं लगाया जाता? क्यों, पाकिस्तानी यूट्यूबर ऐसा क्या करते है कि हमे उन्हें बैन करना पड़ता है?
दिलीप मंडल@Profdilipmandal

राज ठाकरे की यही राजनीतिक हैसियत है कि उनका बेटा चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया और वे अब उद्धव ठाकरे के दम पर कूद रहे हैं, जो प्रशांत किशोर के पास मदद मांगने गए थे। क्या पीके को मराठी आती थी?
प्रकाश सिंह@prakashnaraya18

'बिग ब्यूटीफुल बिल' के जरिये ट्रंप ने देश में अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाने वाली कवायद शुरू कर दी है। अमेरिकी सरकार पर कर्ज बढ़ने वाल है। भारत व्यापार समझौता करते यह समय ध्यान रखे कि उसे एक राजनीतिक नेता से नहीं, बल्कि कारोबारी राष्ट्रपति के साथ करार करना है।
मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में बाधक बन रहा है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

बिहार विस चुनाव को लेकर चिराग पासवान का रवैया राजग खेमे में चिंता पैदा करने वाला है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

मरना-जीना साथ है रहना-खाना साथ,
हम अपनी लेंगे निपट जब विराड़ेगी बात।
जब विष देही बात बनी मत बात बहादुर,
दुर्वे-यादव आपचढ़ाओ मत अपना सुर!
छोड़ खाड़ घर वार पलायन पढ़ता करना,
यदि देते तुम काम यहां क्यूं पढ़ता मरना!!
- ओमप्रकाश तिवारी

हरियाणा डायरी

शहरी निकायों को सशक्त बनाने का सोच

अनुराग अग्रवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, हरियाणा

देशभर के शहरी निकायों के अध्यक्षों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में जहां विभिन्न नगर निगमों की अच्छी व सकारात्मक पहल को समझने और उन्हें अपने निकायों में लागू करने का मौका मिला, वहीं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पंचायती राज, सहकारी संस्थाएं व महिला सशक्तीकरण पर आधारित सम्मेलनों के आयोजन की राह भी तैयार हुई है।

हरियाणा विधानसभा की मेजबानी में गुरुग्राम के मानेसर में हुआ देशभर के शहरी निकायों के अध्यक्षों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। इस सम्मेलन में शहरी निकायों को जहां एक दूसरे के अच्छे कार्यों से सीख लेने की प्रेरणा मिली, वहीं शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के रास्ते भी सुझाए गए। केंद्र व राज्य सरकारों का पूरा जोर इस बात है कि शहरी निकाय अपनी आय के संसाधन स्वयं विकसित करें, ताकि वे सरकारों पर निर्भर न रह सकें। शहरी निकायों के सम्मेलन में लखनऊ, सूरत, इंदौर और पुणे नगर निगमों ने कूड़ा प्रबंधन, सीवर के पानी को शोधित करने तथा कमाई के साधन बढ़ाने की कई ऐसी परियोजनाओं को साझा किया, जो विभिन्न राज्यों के लिए अनुकरणीय साबित हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। शहरी निकायों की मजबूती, महिला व युवा कल्याण और पंचायती राज व सहकारी संस्थाओं की मजबूती इस लक्ष्य को हासिल करने में बहुत मददगार साबित होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी निकायों के सम्मेलन में स्पष्ट संकेत दिया कि शहरी निकाय जनप्रतिनिधि यदि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कदम बढ़ाएं तो वे निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्र में ऊर्जावान बदलाव ला सकते हैं। केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन व शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लोकसभा और विधानसभाओं की तरह शहरी स्थानीय निकायों में सत्र आयोजित करने पर जोर दिया, जिनका संचालन लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की तरह चयनित व्यक्ति करे, ताकि निष्पक्ष तौर पर काम करने की कार्य पद्धति विकसित हो सके। क्षमता निर्माण में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में ओम बिरला। बीच में। और नायब सिंह सैनी। बाएं से दूसरे। व अन्य नेता। फाइल

हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण व शहरी निकाय मंत्री बिपुल गोयल की देखरेख में हुए शहरी निकायों के सम्मेलन में कूड़ा निस्तारण और कचरा प्रबंधन की उन्नत तकनीकों को विकसित करने तथा विभिन्न राज्यों में चल रही सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस को अपनाने पर जोर दिया गया। पूरा फोकस कूड़े से धन अर्जित करने पर रहा। इसके लिए लखनऊ, सूरज, पुणे और इंदौर ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किए। शहरी स्थानीय निकायों के आर्थिक संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि का रोडमैप पेश किया। शहरों में लगे कूड़े के ढेर कैसे हटाए जा सकते हैं और उन्हें स्वच्छ व सुंदर बनाने की तकनीक कैसे अमल में लाई जा सकती है, इस सम्मेलन में देखने-समझने को मिली। सूरत, इंदौर, पुणे और लखनऊ के नगर निगमों के चयनित अध्यक्षों और अधिकारियों की कार्यप्रणाली कम से कम हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, पंचकूला व करनाल शहरों के लिए जबरदस्त सीख साबित हो सकती है, जहां कूड़े के ढेर और गंदगी के साथ अवरुद्ध सीवर सिस्टम पूरे विकास की पोल खोल रहा है। गुरुग्राम में हलकी बरसात के बावजूद बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं।

हरियाणा का कोई भी शहर जीरो वेस्ट की श्रेणी में नहीं आ पाया है। प्रदेश के शहरों में कूड़ा प्रबंधन और कूड़ा संग्रहण पर करोड़ों रुपये की रकम खर्च की जा रही है, लेकिन शहरों में जगह-जगह कूड़े के ढेर नजर आते हैं। लोगों की सहभागिता भी नहीं दिखाई देती है। कूड़ा संग्रह करने वाली गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम तो लग दिए गए हैं, लेकिन वह काम नहीं कर रहे हैं। कूड़ा निस्तारण वाली कंपनियां मोटे-मोटे बिल हड़प कर जाती हैं, लेकिन कूड़ा साफ नहीं होता।

सूरत नगर निगम सीवर से निकले पानी को शोधित कर उद्योगों को 140 करोड़ में बेच रहा है। इससे नगर निगम को राजस्व का लाभ मिल रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा सोनीपत समेत कई शहरों का गंदा पानी नलों में बह रहा है। एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं, जो अधिकतर बंद रहते हैं। उद्योगों में भूजल का ही प्रयोग किया जा रहा है। पाकों में सिंचाई तक नहरी पेयजल से ही हो रही है। निकाय मंत्री बिपुल गोयल का कहना है कि हम जल्दी ही विधान के साथ बैठकर कर दूसरे राज्यों के निकायों की अच्छी प्रैक्टिस को अपने यहां लागू करेंगे, जो कि किसी चुनौती से कम नहीं है।

मंथन

सेना के आधुनिकीकरण का समय

वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि भारत अपनी सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक युग के अनुरूप मजबूत और सक्षम बनाने की ओर ध्यान दे

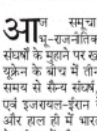

राहुल पाण्डेय
शोधार्थी, पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र, जेएनयू

आज समूचा विश्व कई भू-राजनीतिक एवं सैनिक संघर्षों के मुहाने पर खड़ा हुआ है। रूस-यूक्रेन के बीच में तीन साल से अधिक समय से सैन्य संघर्ष, इजरायल-हमास एवं इजरायल-ईरान के बीच में संघर्ष और हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य संघर्ष यह प्रदर्शित करने के लिए काफी है कि दुनिया एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। बीसवीं सदी के पहले पखवाड़े में भी यही दृश्य था और उन्नीसवीं सदी के शुरू में भी। इस वैश्विक अस्थिरता और सैन्य संघर्ष के तौर में, जहां परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की रणनीतियां काफी उग्रता से सामने आ रही हैं और तकनीकी रूप से युद्ध जटिल होता जा रहा है, इस दौर में भारत जैसे देश के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक युग के अनुरूप युद्ध लड़ने और जीतने के लिए मजबूत एवं सक्षम बनाना आवश्यक हो गया है।

भारत की सशस्त्र सेनाएं विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती हैं। हर साल लगभग 60 हजार से 70 हजार सैनिकों की भर्ती होती है। वर्ष 2022 में सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की है, जिसके तहत सैनिकों की सेवा अवधि घटाकर कुल चार वर्ष कर दी गई है, जिसमें छह महीने प्रशिक्षण और लगभग साढ़े तीन वर्षों की सेवा शामिल है। यह योजना युवा वर्ग को सेना में शामिल करने और सेना को युद्ध के लिए मजबूत बनाने के लिए थी। इसके अलावा, सेना की अर्थांतर्गत को सही से उपयोग में लाने के लिए था जिसमें पेंशन के व्यय को कम करना और उससे बचाई गई मुद्रा को सेना को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए लगाया जाना था।

विश्व में बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीतिक तनाव इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में युद्ध की प्रकृति और स्वरूप में बदलाव आएगा। केवल पारंपरिक हथियार और युद्ध रणनीति से काम नहीं चलेगा, बल्कि सइबर युद्ध, हाइब्रिड युद्ध और तकनीकी श्रेष्ठता के लिए भी तैयार रहना होगा। भारत को ऐसे समय में अपनी सेना की लड़ाकू क्षमता को और अधिक चुस्त, प्रशिक्षित और उन्नत बनाना होगा।

जवानों का व्यक्तिगत कल्याण, उनके परिवार आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति और उसके लड़ने की छमता एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यदि सैनिक का परिवार आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रहेगा, तभी सैनिक युद्ध के लिए पूरी ताकत और उत्साह के साथ तैयार हो पाएगा। सैनिक की सेवा अवधि के बाद उसे उचित पेंशन और वित्तीय सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, ताकि वह न केवल अपने परिवार की देखभाल कर सके, बल्कि समाज में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत कर सके।

सैन्य सुधार : अग्निवीर योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। इसके तहत सैनिकों को केवल चार वर्ष की सेवा अवधि दी जाती है, जिसमें छह महीने प्रशिक्षण शामिल हैं। यह अवधि सैनिकों को तकनीकी और सामरिक कौशल सीखने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षण अवधि को दो वर्षों तक बढ़ाया जाए और सेवा अवधि आठ से 12 वर्ष के बीच निर्धारित की जाए। इससे सैनिक अधिक अनुभव हासिल करेंगे, उनकी युद्धकौशल बेहतर होगी और वे सेना में अधिक समय तक योगदान दे सकेंगे।

दूसरा, सेवा समाप्ति पर सैनिकों को एकमुश्त नकद राशि के रूप में लगभग एक करोड़ रुपये देने का प्रविधान भी किया जाना चाहिए। यह राशि उनके जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाएगी और उन्हें उस राशि को अच्छे से निवेश करने में मदद मिलेगी। तीसरा, इसके साथ ही सरकार को सैनिकों को वित्तीय योजना, निवेश के विकल्प और शेयर बाजार के बारे में सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सेवा शुरू करनी चाहिए। इससे सैनिक अपने पैसों को सही दिशा में निवेश कर पाएंगे, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता और मजबूत होगी। यह कदम पेंशन पर होने वाले भारी खर्चे को भी कम कर सकता है और रक्षा बजट में बचत होगी।

चौथा, सैनिकों के वेतन को बढ़ाकर उनके मनोबल को बढ़ावा देना चाहिए। सेवा अवधि कम होने के कारण वेतन में वृद्धि सैनिकों को आर्थिक असुरक्षा से बचाएगी और सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए आकर्षक विकल्प बनेगी। उच्च वेतन न केवल सैनिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि इससे उनकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी, जो सीधे तौर पर उनकी युद्धक क्षमता को बढ़ाएगा। अधिक वेतन देश में लोगों के व्यय करने को प्रोत्साहित करेगा जो आर्थिकी के लिए जरूरी है।

अगर हम केवल हथियार और तकनीक में निवेश करें, लेकिन सैनिकों की व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को नजरअंदाज करें, तो हम अपनी सेना की क्षमता को पूरी तरह विकसित नहीं कर पाएंगे। सैनिक तभी देश के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खड़ा हो सकता है, जब उसे और उसके परिवार को पूर्ण सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक स्थिरता मिले। इसलिए भारतीय रक्षा मंत्रालय को अग्निवीर योजना समेत अन्य सैन्य नीतियों की पुनः समीक्षा करनी चाहिए, जिससे सैनिकों को न केवल बेहतर सेवा अवसर मिले, बल्कि वे अपने भविष्य के लिए भी आश्वस्त हों।

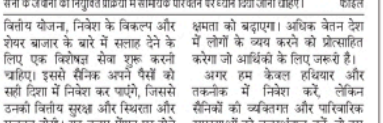

सेना के जवानों की नियुक्ति प्रक्रिया में सामयिक परिवर्तन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फाइल

****

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 09-07-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMH16 User: dilip.lal Time: 07-08-2025 21:12 Color:

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 9 जुलाई 2025

व्यवस्था की नाकामी

बिहार के पूर्णिया में तंत्र-मंत्र के शक में एक ही परिवार के पांच लोगों को जिंदा जला दिया गया। यह घटना राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए जितनी चिंताजनक है, उतनी की शर्मनाक है शिक्षा व्यवस्था के लिए। जब भारत स्पेस में कदम रख संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहा है, तब इस तरह की वारदात बताती हैं कि समाज का एक तबका कितने गहरे अंधविश्वास में डूबा हुआ है।

कानून का डर नहीं । पीड़ित परिवार की एक महिला झाड़-फूंक करती थी। जब कुछ दिनों पहले गांव के एक बच्चे की मौत बीमारी के बाद हुई, तो लोगों का शक उस महिला और उसके परिवार पर गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले भी इस गांव में कुछ लोगों की जान बीमारी से गई थी। लेकिन, लोगों को लगा कि इन सबके पीछे वही पीड़ित परिवार है। पहले पंचायत हुई और फिर भीड़ ने नृशंसता दिखाते हुए वारदात को अंजाम दिया। यह स्थिति तब है, जब राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा बना हुआ है - पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या के बाद से सरकार अपनी छवि बचाने की कोशिश में है।

AI Image

पूर्णिया में 5 की हत्या

शिक्षा में पिछड़ापन । पूर्णिया बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में आता है। घटना जिस टेटगामा गांव में हुई, वह आदिवासियों का है। यहां के लोग अगर आज भी झाड़-फूंक के चक्कर में फंसे हुए हैं और जादू-टोने पर भरोसा करते हैं, तो इसके पीछे पिछड़ापन और अशिक्षा दोनों है। केंद्र की स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट UDISE+ से पता चलता है कि आधुनिक शिक्षा को छोड़ दीजिए, बेसिक सुविधाओं के मामले में भी बिहार के स्कूल बाकी देश से बहुत पीछे हैं।

बदहाल स्कूल । राज्य के केवल 19.6% स्कूलों में कंप्यूटर हैं, जबकि महज 12.1% स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम। देश में ड्रॉपआउट यानी बच्चों के स्कूली पढ़ाई छोड़ने की दर सबसे ज्यादा बिहार में है, 9-10वीं में 25% से भी ज्यादा। ढाई हजार से अधिक स्कूल केवल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं।

बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था । जादू-टोने का लोगों के जीवन में दखल इसलिए भी है क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था खुद बीमार है। पिछले साल आई CAG की रिपोर्ट बताती है कि पूर्णिया के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की 72% कमी है। वैसे, पूरे बिहार में एक डॉक्टर के भरोसे 2,148 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभागों में 49% पद खाली हैं। ऐसे में पूर्णिया की घटना पूरे सिस्टम की नाकामी है और इसकी जिम्मेदारी सभी को लेनी होगी।

इन दिनों

कुछ नहीं, टाइमपास

मृत्युंजय राय

'**क्या कर** रहे हो?', 'कुछ नहीं, टाइमपास।' 1980 के दशक में एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप में अक्सर दोस्तों के बीच बातचीत में 'टाइमपास' शब्द की एंट्री कुछ इसी तरह से होती थी। इसे अलग आयाम मिला टेलीविजन के आने से। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोग उन घरों में उमड़ने लगे, जहां टीवी था। बड़ी संख्या में तब लोगों ने इंदिरा की शव यात्रा और अंत्येष्टि इस तरह से देखी।

1980 के ही दशक में हम लोग, बुनियाद, रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों का प्रसारण टेलीविजन पर शुरू हुआ और टाउनशिप में टेलीविजन सेट्स की संख्या बढ़ती गई। वहीं, 1982 में दूरदर्शन का देशव्यापी प्रसारण शुरू हुआ था। 1991 में नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की और देश में निजी और विदेशी टीवी चैनलों को प्रसारण की अनुमति मिली। इसी साल देश में CNN पर लोगों ने खाड़ी युद्ध का लाइव टेलीकास्ट देखा। अगले साल रूपर्ट मर्डोक के स्टार टीवी और सुभाष चंद्रा के जी टीवी ने प्रसारण शुरू किया और मनोरंजन की दुनिया पूरी तरह बदल गई।

यह ग्रोथ हैरान करने वाली थी, लेकिन टाइमपास इकॉनमी ने 1990 के दशक के आखिर और अगले तीन दशकों में जो उड़ान भरी, उसके आगे यह चमत्कार बहुत बौना लगने लगा है। 1998 में अमेरिका में गूगल की स्थापना हुई। 2004 में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च की, 2005 में यूट्यूब का जन्म हुआ। जकरबर्ग की फेसबुक (नया नाम मेटा) की ग्रोथ में वट्सऐप और इंस्टाग्राम को खरीदने से काफी तेजी आई। ये सभी आज यूजर्स के लिए 'टाइमपास' का जरिया हैं।

फिर 2016 में आई रिलायंस जियो इंफोकॉम, जिससे विडियो कंटेंट की ग्रोथ को पर लग गए। आज इंटरनेट का सबसे अधिक इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। लेकिन अगर समय ही पैसा है तो क्या खाली समय का इस्तेमाल अधिक कमाई के लिए नहीं करना चाहिए? 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पति-पत्नी, अभिजीत बनर्जी और एस्तर डुफ्लो ने अपनी किताब 'पुअर इकनॉमिक्सः रीथिंकिंग पुवर्टी एंड द वेज टु फाइंड इट' में सुलझाने की कोशिश की थी। शोध से उन्हें पता चला कि गरीब अतिरिक्त पैसा मिलने पर उससे टेलीविजन खरीदते हैं या त्योहारों में खर्च करते हैं या बढ़िया खाना खाते हैं। उन्होंने लिखा, 'इस शोध से पता चला कि जिस चीज से जिंदगी कम बोरिंग होती है, वह गरीबों की प्रायॉरिटी होती है। उन्हें सिर्फ लंबी उम्र के लिए न्यूट्रिशन ही नहीं चाहिए। उन्हें लंबी जिंदगी जीने की वजह भी चाहिए।'

एकदा

दानी से बड़ा याचक

छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु संत रामदास बड़े ही तपस्वी, त्यागी और ज्ञानी थे। एक दिन संत रामदास भिक्षा मांगते हुए एक गांव पहुंचे। वहां के एक जमींदार के विशाल भवन के दरवाजे पर खड़े होकर वह आवाज लगा रहे थे। जमींदार ने खिड़की से देखा कि एक साधु खड़ा है। जमींदार को गांव के सबसे धनवान व्यक्ति होने का गुमान था। रामदास को देखते हुए उसने व्यंग्य में कहा, 'आप तो बड़े तेजस्वी लगते हैं, लेकिन दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाते हैं?' रामदास मुस्कराए और बोले, 'मैं अपने लिए नहीं, समाज के लिए मांगता हूं। और भिक्षा लेना कोई अपमानजनक कार्य नहीं, जब उसका उद्देश्य परोपकार हो।' जमींदार हंसते हुए बोला, ' आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, बड़ा कौन- दाता या याचक?' रामदास बोले, 'याचक बड़ा है।' यह सुनकर जमींदार हंसी उड़ाते हुए बोला, 'वाह! अब दाता छोटा हो गया? अरे, हम जैसे लोग तो खाना देते हैं, वस्त्र देते हैं।' रामदास ने कहा, 'याचक इसलिए बड़ा है क्योंकि वह दाता के भीतर दया, करुणा और सेवा की भावना जगाता है। दानी के भीतर छिपा भगवान, याचक ही तो बाहर लाता है।' यह सुनकर जमींदार चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।

Subrata Dhar

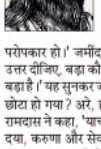

संकलन : रिंकल शर्मा

अभी तक तीन जजों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, एक पास नहीं हुआ तो दो में पहले ही इस्तीफा

जस्टिस वर्मा मामले से क्या बदलेगी हिस्ट्री

राजेश चौधरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच करने वाली तीन सदस्यीय समिति की हाल में आई रिपोर्ट ने नकदी बरामदगी मामले में दी गई साजिश की थियरी को खारिज करते हुए सवाल उठाया कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। इस रिपोर्ट के आधार पर, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की।

सनसनीखेज मामला । एक मीडिया रिपोर्ट में नकदी बरामदगी की खबर सामने आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय ने प्रारंभिक जांच की थी। 14 मार्च की रात 11:35 बजे न्यायमूर्ति वर्मा के दिल्ली स्थित आवास पर लगी आग में कथित तौर पर नोटों के बंडल जले थे और बरामद किए गए थे।

जांच समिति बनी । इसके बाद जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया और उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 22 मार्च को तीन जजों की जांच समिति का गठन किया। फिर 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि जस्टिस वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए।

महाभियोग मे मुश्किल

- प्रक्रिया बड़ी लंबी और जटिल है
- दोनों सदनों में चाहिए दो तिहाई मत
- इस्तीफा देकर हटने का भी विकल्प

पुलिस की लापरवाही । अपनी रिपोर्ट में कमिटी ने दिल्ली पुलिस के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि उसने सरकारी बंगले के स्टोररूम में आग बुझाने के दौरान मिले नोटों को जब्त नहीं किया। समिति ने यह भी कहा कि पुलिस और दमकल कर्मियों द्वारा मौके से बिना किसी पंचनामा या जब्ती मेमो के चले जाना 'लापरवाहीपूर्ण' था।

जस्टिस वर्मा का दावा । कमिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सबूतों से यह संकेत मिला कि वहां बड़ी मात्रा में नकदी मौजूद थी, जो न्यायमूर्ति वर्मा के इस दावे के विपरीत था कि उनके परिसर में कोई नकदी थी ही नहीं। समिति ने माना कि बरामद मुद्रा की सटीक मात्रा का पता न चल पाना कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। न्यायमूर्ति वर्मा के रुख को खारिज करते हुए कमिटी ने पूछा कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई।

संसदीय पैनल के सवाल । 24 जून को इस संदर्भ में संसदीय पैनल की बैठक में कई सांसदों ने यह सवाल उठाया कि कथित नोट बरामदगी के मामले में अब तक प्राथमिकी (FIR) क्यों दर्ज नहीं की गई है। सांसदों ने यह भी मांग की है कि जजों के लिए आचारसंहिता होनी चाहिए, और उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम पांच वर्षों तक किसी सरकारी पद या नियुक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

महाभियोग का रास्ता । संविधान के अनुच्छेद- 124 (4), 217 और 218 में संविधान के उल्लंघन और गलत व्यवहार और अक्षमता से संबंधित मामले में किसी जस्टिस को हटाने का प्रस्ताव लाने का प्रावधान है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। अगर लोकसभा में इसे पेश करना है तो इसके लिए कम से कम एक सौ सांसदों के दस्तखत होने जरूरी हैं। वहीं राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत होने चाहिए। महाभियोग के अंतिम चरण में प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित करना होता है।

सभापति के अधिकार । जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उसके सभापति इसे खारिज कर सकते हैं। ऐसा करने पर मामला वहीं खत्म हो जाता है। सभापति के प्रस्ताव स्वीकार करने की स्थिति में तीन मेंबरों की समिति बनाई जाती है। समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और एक जाने-माने जूरिस्ट होते हैं। समिति देखती है कि जो आभियोग लगाया गया है, वह ठहरता है या नहीं। जिन पर अभियोग लगाया गया है उन्हें समिति के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। मामला बनता हो तो प्रस्ताव सदन के सामने भेज दिया जाता है।

क्या होगा आगे । भारतीय संसदीय इतिहास में आज तक किसी जस्टिस को महाभियोग के जरिये हटाया नहीं गया है। हालांकि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू जरूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नोटिस को तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था। 1993 में जस्टिस वी. रामास्वामी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वह लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। जस्टिस पीडी दिनाकरण के मामले में पहल हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के मामले में भी यही हुआ। प्रस्ताव आया लेकिन कार्यवाही पूरी होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में घटनाक्रम कैसा मोड़ लेता है इस पर पूरी कानूनी बिरादरी की नजर है।

डॉनल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल (BBB) अब कानून बन गया है। विशेषज्ञों को डर है कि यह बिल अमेरिका को और पीछे धकेल देगा। जितना बड़ा यह बिल है, उतनी ही बड़ी इसके फायदे-नुकसान को लेकर हो रही बहस भी है। समझते हैं इस बिल के बारे में।

कितना ब्यूटीफुल है ट्रंप का बिग बिल?

बिग बिल

- लगभग एक हजार पन्नों का है बिल
- रिपब्लिकन सांसदों ने बगैर ठीक से पढ़े की वोटिंग
- **214** के मुकाबले निचले सदन में **218** वोटों से पास हुआ
- जल्दबाजी में पास हुआ, छुपे प्रावधानों का डर

किसे फायदा

- अमीर और हाई-इनकम वालों की बचत
- **$2,200** चाइल्ड टैक्स क्रेडिट बढ़ा
- **$7,500** EV पर क्रेडिट खत्म, बढ़ेगी पेट्रोल-कारों की मांग
- हथियार बनाने वाली कंपनियों को

किसे नुकसान

- **1.2** करोड़ अमेरिकी परिवारों का स्वास्थ्य बीमा रद्द होगा
- **$68.6B** खाद्य सहायता में कटौती
- **40-42** मिलियन लोगों के लिए भोजन संकट
- EV कंपनियों की बिक्री, जॉब व निवेश में गिरावट

बड़ी कटौती

- स्वास्थ्य बीमा में कटौती, ओबामाकेयर की सब्सिडी खत्म
- ग्रीन एनर्जी सब्सिडी 2027 तक समाप्त, कम बनेगी ग्रीन बिजली
- **$10000** तक टैक्स में कटौती सीमित (स्टेट और लोकल)
- बच्चों को घर खरीदवाने वाले अभिभावकों की ब्याज छूट खत्म
- धर्मार्थ योगदान, दान आदि में भी छूट से कटौती
- US में बनी कार खरीदने पर इनकम टैक्स में कटौती
- कुछ बड़े विश्वविद्यालयों पर लादी फीस

बिग बजट घाटा

- 10 वर्षों में बजट घाटा 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का डर
- शुरुआत में जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था पर बोझ
- ब्याज दरें बढ़ेंगी, खर्च घटाना, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा

बड़ा खर्च

- **$5000B** तक US की उधार लेने की सीमा बढ़ाई
- **$300B** का प्रावधान सीमा सुरक्षा के लिए
- **$46.5B** बॉर्डर पर दीवार के लिए
- **$45B** अवैध प्रवासियों की हिरासत लिए
- **$25B** का फंड गोल्डन डोम को
- **$10B** मंगल मिशन के लिए, ISS बंद करने के लिए $325M

देशों पर प्रभाव

- US में रह रहे भारतीयों को बड़ी राहत
- क्लीन एनर्जी के फैसले से देशों के सोलर व विंड प्रॉजेक्ट्स पर असर
- US के कर्ज से डॉलर की वैल्यू पर दबाव
- अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर पर टैक्स दर घटाकर 1% किया
- EV फैसले से चीन-भारत की सप्लाई चेन पर उलटा असर
- भारत समेत कई देशों की करंसी में गिरावट का बड़ा डर

टैक्स कटौती से खपत बढ़ सकती है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा खर्च में कटौती गंभीर समस्या बन सकती है। ट्रंप उन कंपनियों को लाभ नहीं देंगे, जिनकी चेन खासतौर से चीन से जुड़ी है। रक्षा खर्च में बढ़ोतरी संकेत देती है कि US शांति की उम्मीद नहीं कर रहा। - **नीलांजन घोष**, VP, डिवेलपमेंट स्टडीज, ORF

ग्राफिक : राहुल पांडेय

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

गुरु की दिव्य ज्योति से जगमगा उठता है शिष्य

सुरक्षित गोस्वामी

गुरु शिष्य के भीतर छिपी असीम संभावनाओं के द्वार खोल देता है, जिससे वह अपनी सीमाओं को पार कर अनंत ब्रह्मांड का अंग बन जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। जिनके जीवन में गुरु नहीं हैं, उन्हें श्रद्धा भाव से गुरु की खोज करनी चाहिए। जब गुरु मिल जाएं, तो नतमस्तक होकर अपना अहंकार उनके चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। जैसे बीज मिट्टी में मिलकर वृक्ष बनता है, वैसे ही शिष्य का समर्पण गुरु वचनों के प्रति हो तो उसका जीवन लहलहा उठता है।

जाग्रत गुरु के समीप आते ही शिष्य भी भीतर से वैसे ही जगमगाने लगते हैं, जैसे एक प्रज्वलित दीपक अनेक दीपकों को रोशन कर देता है। गुरु के प्रति समर्पण होते ही शिष्य के भीतर गुरु तत्व, गुरु कृपा, गुरु ऊर्जा, गुरु स्पर्श और गुरु वाणी अपने आप बहने लगते हैं। गुरु के समक्ष जाते समय धन, मान-सम्मान, कुटुंब या पद-प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं रहना चाहिए, केवल श्रद्धा भाव से नतमस्तक होना चाहिए। जब हम कुछ बनकर गुरु के सामने जाते हैं, तब गुरु कृपा से चूक जाते हैं। गुरु केवल शरीर नहीं, बल्कि एक तत्व है, जो समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। मेरा गुरु या तेरा गुरु शरीर के स्तर पर भिन्न हो सकता है, लेकिन गुरु तत्व एक ही है। गुरु और शिष्य का संबंध आत्मिक होता है, न कि केवल सांसारिक।

गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु से दीक्षा लेने, साधना को मजबूत करने और अपने भीतर गुरु को अनुभव करने का अवसर है। जैसे प्रकाश के होने से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही गुरु के स्मरण से विकार दूर हो जाते हैं। चित्त के अंधकार को मिटाने वाला कोई और नहीं, गुरु ही तो होते हैं। वे ही जीवन जीने की कला सिखाते हैं और मुक्ति की राह दिखाते हैं।

कहते हैं, 'हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहिं ठौर', यानी भगवान रूठ जाएं तो गुरु की शरण मिल सकती है, लेकिन गुरु रूठ जाएं तो कहीं भी ठौर नहीं मिलता। गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म हैं और गुरु में निष्ठा ही परम तप है। गुरु से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भी गुरु सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण करते हैं और श्रीराम गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। सामान्य मनुष्य से लेकर भगवान तक को गुरु की आवश्यकता होती है।

गुरु पूर्णिमा का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन शिव ने दक्षिणामूर्ति रूप में ब्रह्मा के मानस पुत्रों को वेदज्ञान दिया था। यही दिन वेदव्यास जयंती भी है, जिनके सम्मान में इसे 'व्यास पूर्णिमा' भी कहा जाता है।

आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, जिसके बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। साधक इस दिन से चौमासे के चार महीने एक स्थान पर रहकर साधना करते हैं, जिससे गुरु का दिया गया ज्ञान जीवन में उतर सके। यह समय साधना के लिए सबसे उपयुक्त है। मनुष्य जन्म चेतना की ऊंचाइयों को छूने के लिए मिला है, जो बिना गुरु के संभव नहीं।

'देखो, पूरा देश इस लड़ाई में हमारे साथ है'

आनंद वासु

एजबेस्टन टेस्ट में जब भारत ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली, तो टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी 'प्रिंस' से 'किंग' बनने का अपना सफर पूरा कर लिया। हालांकि खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट के लिए कहा जाता है कि बल्लेबाज मैच जिताने के लिए जमीन तैयार करते हैं, जबकि जीत दिलाते हैं गेंदबाज। और यहीं से उभरता है ऐसा नायक, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी - आकाशदीप।

गेंद से जादू । मैच में कुल 10 विकेट लेकर आकाश ने इतिहास रचने में अहम भूमिका निभाई। इस मैदान पर इससे पहले कोई एशियाई टीम टेस्ट मैच नहीं जीती थी। इंग्लैंड ने इस पिच को खासतौर पर बनवाया था जो बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जा रही थी - आकाश ने वहां गेंद से वह कमाल किया, जो दूसरे न कर सके।

शमी की भरपाई । आकाश के पास वह हुनर है, जिसकी कमी मोहम्मद शमी के चोटिल होने की वजह से टीम इंडिया को महसूस हो रही थी। आकाशदीप बॉल को एक ही हार्ड लेंथ पर लगातार फेंक सकते हैं। इस तरह की बोलिंग उनकी muscle memory का हिस्सा बन चुकी है।

मुश्किल सफर । क्रिकेट खेलने का सपना आकाश को बिहार के सासाराम से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर लेकर गया। वहां आकाश के पास क्रिकेट खेलने के लिए न तो पैसे थे और न समय। वह नौकरी की तलाश में निकले थे, लेकिन एक क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन ले लिया। लेकिन 2015 में उन पर दोहरी मार पड़ी - पहले पिता और फिर बड़े भाई की मौत हो गई। आकाश को तीन साल तक खेल से दूर रहना पड़ा। यही नहीं, कोविड के दौरान उनकी चाची और भाभी की मौत हो गई, मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं।

टीम ने किया तैयार । आकाश फिर कोलकाता गए, वहां एक सेकंड डिविजन टीम में जगह बनाई, और जब शमी ने उन्हें बोलिंग के टिप्स दिए तो वह रंग में लौट आए। घरेलू क्रिकेट में वह विकेट लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। हालांकि तब भी किसी को उनसे एजबेस्टन वाले कारनामे की उम्मीद नहीं थी। पहले टेस्ट के दौरान वह अनफिट थे और टीम मैनेजमेंट को हर्षित राणा को बुलाना पड़ा। लेकिन, कोचिंग स्टाफ ने इस दौरान आकाश पर पूरा भरोसा रखा और उन्हें तैयार किया।

कॉमन रूम

गंभीर का भरोसा । आकाशदीप के प्रदर्शन ने पूरे देश में यकीन भरा है। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में भारत का टीम सिलेक्शन रक्षात्मक माना गया था, लेकिन कोच गौतम गंभीर ने शुरू से कहा कि यह टीम 20 विकेट ले सकती है। आकाश के प्रदर्शन ने साबित किया कि घरेलू क्रिकेट पर नजर रखने वाले selectors, प्लेइंग इलेवन में बैलेंस बनाने वाले कोच और मैदान पर टीम को चलाने वाले कप्तान के पास एक स्पष्ट योजना होती है। हां, यह हो सकता है कि बाहर से वह प्लान सभी को न दिखे।

बहन को समर्पित । आकाश ने इस मैच में इतनी जान झोंक दी थी कि पहली बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया कि बोलिंग के दौरान उन्हें असली ताकत कहां से मिल रही थी। उन्होंने अपना प्रदर्शन बहन ज्योति को समर्पित किया, जो कैंसर के स्टेज 3 से जूझ रही हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनके भाई ने पूरे देश के सामने उनके बारे में बात की। आकाश ने बहन को समझाया कि वह भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर कर नहीं पाए। उन्होंने बहन से कहा कि वह बिल्कुल चिंता न करें, 'देखो, पूरा देश इस लड़ाई में हमारे साथ है।'

[illegible]

हिन्दुस्तान 1936

महिलाओं पर दांव

बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 फीसदी सीटें आरक्षित करने के फैसले के गहरे निहितार्थ हैं। सबसे पहले इस निर्णय के राजनीतिक उद्देश्य को पढ़ा जा रहा है, तो यह स्वाभाविक ही है। बिहार में चार माह के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और पिछले कई चुनाव इस बात के साक्षी हैं कि बड़ी संख्या में महिला मतदाता वहां अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगी हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तो पुरुषों के मुकाबले 5.24 फीसदी अधिक महिलाओं ने वोट डाले थे। साफ है, सत्ता की चाबी वहां महिलाओं ने अपने हाथों में ले ली है और वे धार्मिक व जातिगत आग्रहों से अधिक लैंगिक हितों से प्रेरित हैं। बिहार उन शुरुआती राज्यों में एक है, जिसने पंचायत और स्थानीय निकायों में आधी आबादी के लिए पचास फीसदी सीटें आरक्षित की हैं। इस कदम ने यहां की स्त्रियों में जबर्दस्त राजनीतिक जागरूकता पैदा की है। ऐसे में, हरेक राजनीतिक दल इस वर्ग को आकर्षित करने में जुट गया है। राजद-कांग्रेस-वाम दलों का महागठबंधन 'माई-बहिन मान योजना' के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये देने का वायदा कर चुका है, तो राजद नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी और डोमिसाइल के मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में, नीतीश सरकार के इस नीतिगत दांव को समझा जा सकता है।

राज्य सरकार का यह फैसला सामाजिक लिहाज से भी काफी प्रभावशाली हो सकता है। पिछले डेढ़ दशक में बिहार में बड़ी संख्या में लड़कियां कॉलेज-यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेकर निकली हैं और राष्ट्रीय जागरूकता ने उनके भीतर भी अपने पैरों पर खड़े होने की ललक पैदा की है। सूचना क्रांति, बढ़ती अपेक्षाओं और सामंती बंधनों के ढीले पड़ते जाने के कारण अब ग्रामीण बिहार की बेटियां भी ऊंचे सपने संजो रही हैं। गांव-गांव में स्कूलों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनके पास भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने के मौके हैं, इसके लिए उन्हें बस शिक्षित होने की जरूरत है। फिर सरकारी क्षेत्र की नौकरियों को लेकर, खासकर महिलाओं में खूब आकर्षण है। बड़ी संख्या में महिला शिक्षा मित्रों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने महिलाओं को लेकर गांव-समाज की सोच को बदला है। ऐसे में, सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं का आरक्षण एक बड़े सामाजिक बदलाव का वाहक बन सकता है।

यदि देश की बेटियों को उनकी योग्यता के अनुसार घर के आस-पास ही नौकरी और रोजगार के अवसर मिल जाएं, तो इससे अधिक मुनासिब और क्या होगा?

यह सर्वविदित तथ्य है कि दिन-ब-दिन शैक्षिक क्षेत्र की लैंगिक खाई कम हो रही है। यही नहीं, अब सभी प्रदेशों की बेटियां देश के दूसरे हिस्सों में नौकरी के लिए जाने लगी हैं। बिहार की लड़कियां देश के तमाम महानगरों में नौकरीशुदा हैं, तो खुद वहां पर शिक्षकों की हालिया भर्तियों में एक दर्जन से भी अधिक प्रदेशों की लड़कियां इंटरव्यू देने पहुंची थीं। उनमें से अनेक सफल भी रहीं और बाकायदा वहां के स्कूलों में पढ़ा रही हैं। निस्संदेह, सैद्धांतिक स्तर पर यह एक स्वागत योग्य बदलाव है, मगर व्यावहारिक रूप से देखें, तो देश में महिला सुरक्षा अब भी चिंता का बड़ा विषय है। ऐसे में, यदि बेटियों को उनकी योग्यता के अनुसार घर के आस-पास ही रोजगार के अवसर मिल जाएं, तो यह अधिक मुनासिब माना जाएगा। इस नजरिये से नीतीश सरकार का फैसला स्वागत-योग्य है। अन्य राज्य सरकारों को भी महिलाओं के लिए ऐसे विशेष प्रबंध करने चाहिए, ताकि वे न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें, बल्कि देश की तरक्की में बराबर की हिस्सेदारी निभा सकें। ऐसे फैसलों का विस्तार निजी क्षेत्र तक होना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 09 जुलाई 1950

कोरियाई युद्ध से वैश्विक चिंता

कोरिया! एशिया के सुदूर-पूर्व में स्थित इस छोटे-से देश ने आज समस्त संसार का ध्यान अपनी ओर केन्द्रित कर रखा है। द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रभाव से पीड़ित और जर्जरित जनता सोचने लगी है कि कहीं यह देश तृतीय विश्व-युद्ध के लिए 'पोलैंड' तो न बन जायेगा, जिसका अर्थ आधुनिक सभ्यता के महानाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता।

यदि हम वहां के गत सप्ताह के घटना-चक्र पर दृष्टिपात करें तो मालूम होगा कि उत्तरी कोरियाई सेनाओं की अबाध प्रगति पूर्ववत् जारी है। दक्षिणी कोरिया की सेनाओं की कमर प्रायः टूट चुकी है और उनकी सहायता को पहुंची हुई अमरीकी सेनाओं की स्थिति भी अधिक आशाप्रद नहीं। पहली करारी हार का स्वाद वे चख चुकी हैं और उन्हें सुयोग जैसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे से भी हाथ धोना पड़ा है। आखिर, इसका कारण क्या है? अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि मौसम अनुकूल न होने के कारण उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सफलतापूर्वक हवाई कार्रवाई नहीं की जा सकती। फिर सुयोन के पतन के बाद दक्षिणी कोरिया में उनके पास पूसान ही एकमात्र हवाई अड्डा बचा है, जिससे उन्हें हवाई आक्रमणों के लिए जापान-स्थित हवाई अड्डों से काम लेना पड़ता है। अमरीकी अधिकारियों की बात कुछ-कुछ समझ में आ सकती है, पर पूरी तरह से नहीं। सच बात यह है कि उन्होंने उत्तरी कोरिया की सैनिक शक्ति को आंकने में भूल की। उनका खयाल था कि हवाई आक्रमण करके ही वे उसे परास्त कर देंगे। अब तक के समाचारों ने उनकी इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया है। इसी कारण वे स्थल सेनाएं भी रण-क्षेत्र में उतारने के लिए बाध्य हुए। किन्तु इससे भी स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ मालूम होता।

हाल में अमरीका में आंशिक भर्ती का आदेश जारी किया गया है। कुछ समय पूर्व वाशिंगटन से घोषणा की गयी थी कि कोरियाई युद्ध के कारण देश में अतिरिक्त भर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अमरीकी कांग्रेस के एक सभासद ने उत्तरी कोरिया पर अणु-बम छोड़ने का भी सुझाव दिया। इधर पासों के रुख में भी काफी परिवर्तन हो गया है। अमरीका और ब्रिटेन के अनेक पत्र इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि कोरिया का मामला वर्तमान गति से शीघ्र सुलझने की आशा नहीं।

एक अलग दुनिया रच गए गुरु दत्त

हिंदी सिनेमा को ईंट-दर-ईंट पुख्ता करने वालों में एक सशक्त नाम हैं गुरु दत्त। आज उनकी 100वीं जयंती पर याद करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है।

वहां सेव करें

जयंती रंगनाथन | वरिष्ठ पत्रकार

वह 1990 की अप्रैल का एक चिपचिपाता दिन था, जब मैं मुंबई में सदाबहार अभिनेता देव आनंद से उनके दफ्तर में मिली थी। बातचीत के लिए उन्होंने अपने दफ्तर बुलाया था। साक्षात्कार की शुरुआत में ही गुरु दत्त का जिक्र आगया। अपने बेहतरीन और थोड़े दीवाने दोस्त को याद करते हुए देव साहब ने कहा था, 'मैं और गुरु संघर्ष के साथी थे। प्रभात स्टूडियो में वह बतौर सहायक फिल्म निर्देशक व सहायक नृत्य निर्देशक संघर्ष कर रहा था और मैं नायक बनने की जद्दोजहद में लगा था। फाकाकशी के दिनों में न जाने कितनी बार मैं उसके घर गया, उसकी मां के हाथों का बना खाना खाया। वह अपनी हर चीज मेरे साथ बांटता था, सपने भी। हमने तय किया था कि सफलता भी हमारी साझी ही होगी। मगर जब दुख बांटने की बात आई, तो मेरा दोस्त अपना वादा भूल गया।'

सन् 1951 में संघर्ष करने वाले दोनों दोस्तों की किस्मत बदल गई। देव साहब ने अपने 'नवकेतन फिल्म्स' के तले बनने वाली पहली फिल्म *बाजी* के निर्देशन की कमान गुरु दत्त को सौंप दी। रहस्य, रोमांच और अपराध से लबरेज इस फिल्म को याद करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इस फिल्म ने दो महान फिल्म विभूतियों को जन्म तो दिया ही, साथ ही उन्हें इससे जीवन संगिनियां भी मिलीं। गुरु दत्त को फिल्म की गायिका गीता दत्त और देव आनंद को फिल्म की सह कलाकार कल्पना कार्तिक।

गुरु दत्त, जिनका पैदाइशी नाम वसंत कुमार पादुकोण था, बचपन से ही थोड़े मूडी, थोड़े गुस्सैल और खूब कल्पनाशील थे। उनकी मां वासंती ने सालों पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जब गुरु दत्त दो साल के थे, बहुत बीमार पड़े। उस वक्त एक साधु ने सलाह दी कि इस बच्चे का नाम बदल दो। इस तरह उनका नाम गुरु दत्त पड़ा। बेंगलुरु में जन्मे कन्नड़ भाषी गुरु दत्त की शिक्षा-दीक्षा कोलकता में हुई, जहां उनके पिता नौकरी करते थे। बचपन अभावों में बीता। दसवीं के बाद ही नौकरी करनी पड़ गई। गुरु दत्त को नृत्य सीखने में गहरी दिलचस्पी थी। शिमला में उदयशंकर के नृत्य अकादमी में उन्हें छात्रवृत्ति मिली। दूसरे महायुद्ध के शुरू होते ही अकादमी बंद हो गई और नौकरी तलाशते हुए गुरु दत्त मुंबई आ गए।

जिन दिनों वह मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने *कशमकश* नाम से एक कहानी लिखी। उस वक्त किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन इस कहानी पर खुद गुरु दत्त *प्यासा* फिल्म बनाएंगे और वह *टाइम* पत्रिका के 2005 के अंक में 20वीं सदी की विश्व की महानतम 100 फिल्मों में शुमार हो जाएगी।

गुरु दत्त ने जब अपना प्रोडक्शन शुरू किया, उनकी दृष्टि स्पष्ट थी। उसूल बनाया कि बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होने वाली फिल्में बनाएंगे। सफल फिल्मों के बाद ही अपने मन की गंभीर फिल्म को हाथ लगाएंगे। *आर-पार* और *मिस्टर ऐंड मिसेज 55* फिल्मों की कामयाबी के बाद उन्होंने तय किया ऐसी फिल्म बनाने का, जो उनके दिल के करीब हो। *प्यासा* बनाना आसान नहीं था, ऐसी फिल्म, जो जिंदगी के अंधेरे कोनों को छूती है, निराशा की बात करती है और असली किरदारों की कहानी कहती है। *प्यासा* बनाने के दौरान ही उनका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। जब पहली बार उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। गीता दत्त के साथ उनका विवाह अलगाव के थपेड़े झेलने लगा था।

प्यासा की नायिका वहीदा रहमान ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था, 'गुरु दत्त चाहते थे कि इस फिल्म में नायक की भूमिका दिलीप कुमार निभाएं। उनके मना करने के बाद उन्होंने तय किया कि वह निर्देशन के साथ-साथ अभिनय भी करेंगे। पता नहीं क्यों, उन्हें शंका थी कि वह फिल्म नहीं चलेगी। निजी जीवन में वह निराश रहते थे, लेकिन जैसे ही सेट पर आते एकदम बदल जाते। उनका कहा एक संवाद मेरे साथ हमेशा रह गया, जिंदगी में दो ही तो चीजें हैं- कामयाबी और नाकामी।'

प्यासा 1957 में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला और आलोचकों से सराहना भी मिली। इस फिल्म की अपार सफलता का गुरु दत्त पर खास असर नहीं हुआ। उनके सबसे गहरे मित्र अबरार अल्वी मानते थे कि गुरु दत्त उन दिनों अजीब निर्णय लेने लगे थे, अपने ही बनाए उसूल तोड़ने लगे थे। जैसे *प्यासा* के तुरंत बाद *कागज के फूल* जैसी जटिल और गंभीर फिल्म बनाने का फैसला लेना।

कागज के फूल एक बार फिर से गुरु दत्त की अपनी जिंदगी के कुछ अक्सों पर आधारित थी। उनकी छोटी बहन ललिता लाजमी ने अपने भाई की आत्मकथा *गुरु दत्त : ऐन अनफिनिश्ड स्टोरी* में कहा है, 'भाई की बिगड़ती मानसिक हालत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह रोज अपनी ड्रिंक में नींद की दवाई मिलाकर लेते थे। मुझे फोन करके घर बुलाते, जहां वह अकेले रहते थे, यह कहकर कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जब मैं जाती, तो वह चुप लगा जाते। उन्होंने कभी अपने मन का दर्द किसी से नहीं बांटा, पर उनके आसपास वालों को पता था कि वह किस तरह अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं।'

कागज के फूल की नाकामी ने गुरु दत्त को बुरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद भी उन्होंने फिल्में बनाईं, लेकिन कभी निर्देशन में नहीं उतरे। *चौदहवीं का चांद* एक बेहद कामयाब और चर्चित फिल्म थी। इस फिल्म में वह बतौर निर्माता और कलाकार जुड़े थे। ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। *साहब, बीबी और गुलाम* जैसी फिल्म बनाते समय भी गुरु दत्त लगातार मानसिक संताप और उलझनों से जूझते रहे। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने अपने मित्र और सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति से कहा था, 'मेरे पास सब कुछ तो है, जिसकी कभी तमन्ना की थी। पैसा, शोहरत, नाम, कामयाब फिल्में। फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं?' आज जिस तरह मानसिक बीमारी की बात फिल्म के कलाकार खुलकर कह रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं, अगर गुरु दत्त भी समय रहते अपना इलाज करवाते, तो शायद देश और दुनिया को कई नायाब फिल्मों का तोहफा मिलता।

फिल्मों में छाया और प्रकाश से एक अलग दुनिया रचने वाले, बेशकीमती फिल्में देने वाले, समय से आगे की सोच रखने वाले गुरु दत्त मात्र 39 साल में एक अधूरी लिखी किताब की तरह चले गए। ठीक उसी तरह, जैसे *प्यासा* में उन्होंने अपने किरदार के लिए अंत लिखा था।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

खेलों में भारत को सुपर पावर बनाने की खास पहल

वहां सेव करें

अशोक कुमार | कुलपति, हरियाणा खेल विश्वविद्यालय

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी)-2025 एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी पहल है, जो भारत को वैश्विक खेल शक्तियों की कतार में खड़ा करने वाली है। साल 2001 की नीति से आगे बढ़ते हुए एनएसपी-2025 खेलों को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में रखकर एक नया और व्यापक खाका पेश करती है, ताकि भारत खेलों की दुनिया में सुपर पावर बनने की दिशा में बढ़ सके। यह नीति खेलों को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शैक्षिक सुधार के उपकरण के तौर पर पुनर्परिभाषित करती है।

एनएसपी पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित एक मिशन-दृष्टिकोण है। इसमें एक उल्लेखनीय पहल प्रवासी भारतीय को शामिल करना भी है। आज देश के लगभग 70 प्रतिशत शहरी मधुमेह और मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं। इस लिहाज से यह नीति इसका समाधान भी करती है। इसमें 'फिट वर्कप्लेस इंडेक्स' और 'स्कूल फिटनेस इंडेक्स' जैसे राष्ट्रीय सूचकांक शामिल हैं और '10,000 स्टेप्स ए डे' मुहिम को ध्यान में रखा गया है।

एनएसपी-2025 के साथ भारत अंतरराष्ट्रीय खेलों में केवल भाग लेने के लिए नहीं, बल्कि पदक प्राप्त करने के लिए तैयार होगा।

यह खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों, जैसे अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया से प्रेरणा लेते हुए इनकी शिक्षा के महत्व पर जोर देती है। इन देशों के 35 से 50 प्रतिशत ओलंपिक पदक विजेता विश्वविद्यालयों से ही आते हैं। इस दांचे के तहत स्कूल और विश्वविद्यालय खेलों को पेशेवर रूप में पेश करते हैं। इस नीति के तहत सभी शिक्षण संस्थान खेलों में छात्रवृत्तियां देंगे, बुनियादी ढांचे, खेल विज्ञान और कोचिंग का विकास करेंगे, ताकि संस्थानों में ऐसा तंत्र बन सके, जो अच्छे खिलाड़ियों को पहचान कर उनके समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर पाए।

एनएसपी-2025 सिर्फ नीति नहीं, राष्ट्रीय मिशन है। इसकी सफलता सटीक क्रियान्वयन, पारदर्शिता के अलावा सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थान व समुदाय के बीच निरंतर सहयोग पर निर्भर करेगी। लगभग डेढ़ अरब आबादी वाले भारत के लिए यह समय आ गया है कि हम अपनी क्षमता को पदकों में और अपनी भावना को उद्देश्य में बदलें। एनएसपी-2025 के साथ भारत अंतरराष्ट्रीय खेलों में केवल भाग लेने के लिए नहीं, बल्कि पदक प्राप्त करने के लिए तैयार होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

ब्रह्म से बाहर कुछ नहीं

किसी ने पूछा है कि गुण बंधन बनते हैं, निर्गुण मुक्ति, वह कैसे? ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु की पहचान उसकी विशेषता और माध्यम से होती है। जब कोई वस्तु अपने गुणों या स्वभाव को किसी न किसी रूप में प्रकट करती है, तब मनुष्य उसे जान पाता है। उदाहरण के लिए, जल बहता है, अग्नि जलाती है, रात्रि अंधकारमय होती है और करुणा मन को छूती है। यह सब उनकी आंतरिक प्रकृति के बाहरी रूप से प्रकट होने के कारण होता है। इस प्रकट रूप को ही हम उसका क्रियात्मक या व्यवहारात्मक स्वरूप कहते हैं। ये क्रियात्मक अभिव्यक्तियां वस्तु में निहित गुणों के कारण होती हैं। यदि कोई वस्तु पूर्णतया गुणहीन हो, तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी, और यदि कोई क्रिया नहीं होगी, तो उसकी पहचान भी संभव नहीं होगी।

गुण तीन प्रकार के माने गए हैं- सत्व, रजस् और तमस्। यही त्रिगुण समस्त सृष्टि में क्रियाशील हैं और हरेक वस्तु के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। जिन प्राणियों या वस्तुओं में ये गुण सक्रिय होते हैं, वे किसी न किसी प्रकार के बंधन में होते हैं। यह बंधन केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और चेतना के स्तर पर भी होता है। जब मनुष्य अपने विचारों, इच्छाओं और अहंकार में उलझा रहता है, तो वह वास्तव में त्रिगुणों के प्रभाव में जी रहा होता है। यही उसका बंधन है, और वही उसकी सीमितता का कारण भी है।

ऐसे में, प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्म पूरी तरह से गुणों से रहित है? इसका उत्तर यह है कि बाहरी रूप से वह गुणहीन है, पर आंतरिक रूप से विचारों की निरंतर धारा है। यही विचारधारा ब्रह्म की चेतना है, जिससे समस्त सृष्टि की रचना, पालन और लय होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ब्रह्म के मानस में होती है। वहां भी त्रिगुण सक्रिय होते हैं, पर वे ब्रह्म के नियंत्रण में होते हैं, न कि ब्रह्म उनके अधीन होता है।

ब्रह्म के भीतर यह आंतरिक चेतन प्रवाह निरंतर चल रहा है, लेकिन चूंकि यह चाहा रूप में प्रकट नहीं होता, इसलिए उसे सामान्य इंद्रियों या सोच से समझा नहीं जा सकता। ब्रह्म की चेतना समस्त जीवों के भीतर प्रवाहित हो रही है, परंतु हर जीव की चेतना सीमित होती है। जब कोई जीव इस सीमितता को पार करके ब्रह्म की चेतना से एक हो जाता है, तब वह सृष्टि को उसके मूल रूप में अनुभव कर सकता है। लेकिन उस अवस्था में उसकी व्यक्तिगत सत्ता समाप्त हो जाती है और वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यही ब्रह्म की अद्वितीयता, उसकी अपरिमेय चेतना का स्वरूप है।

ब्रह्म किसी क्रिया से पहचाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है और अनुभव सिर्फ उसी को होता है, जो अपने भीतर की सीमाओं को मिटाकर उस अनंत चेतना से एकरूप हो जाता है।

ब्रह्म किसी क्रिया से पहचाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है और यह अनुभव केवल उसी को होता है, जो अपने भीतर की सीमाओं को मिटाकर उस अनंत चेतना से एकरूप हो जाता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

अश्विनी वैष्णव | रेल मंत्री

एआई के युग में, जब तकनीक हर हफ्ते विकसित हो रही है, वैश्विक संस्थाओं का अस्सी साल से बिना सुधार के रहना अस्वीकार्य है। आप 20वीं सदी के टाइपराइटर पर 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते!

अहम मोड़ साबित होगी अमेरिका पार्टी

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उद्योगपति एलन मस्क के बीच हुए विवाद के बाद 'अमेरिका पार्टी' का जन्म हुआ है। मस्क की यह पार्टी अमेरिकी राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। जिस तरह मस्क ने तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में जोखिम उठाकर क्रांतिकारी बदलाव किए, अब वैसा ही प्रयास वह राजनीति में करना चाहते हैं। सर्वेक्षण भी उनके पक्ष में है, जिसके मुताबिक, 65.4 प्रतिशत लोग मौजूदा दो-दलीय व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और बदलाव चाहते हैं। ऐसे में, मस्क के इस प्रयास को 'राजनीतिक स्टार्टअप' कहना गलत नहीं होगा। अगर वह इसमें सफल रहे, तो यह अमेरिकी राजनीति के लिहाज से इतिहास बनाने जैसा होगा, क्योंकि वहां तीसरे दल की संभावना बहुत कम कारगर साबित हुई है। मस्क के पास अपार संसाधन, वैश्विक पहचान और डिजिटल मंच है, जो उन्हें अपने मतदाताओं से सीधे जुड़ने का खास मौका देता है, लेकिन नीतिगत स्पष्टता, राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक ढांचे की कमी उनकी राह को कठिन बना सकती है। फिलहाल, उनका आंदोलन आकांक्षा और असंतोष का प्रतीक कहा जा रहा है, लेकिन आगामी चुनाव तक यह पार्टी क्या रूप लेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी।

अमृतलाल मारू 'रवि', टिप्पणीकार

मस्क डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने के लिए गंभीर नजर आते हैं। अब देखना यही है कि अमेरिका की राजनीति में अमेरिका पार्टी नई क्रांति साबित होती है या इससे मस्क के सामने नई मुश्किलें खड़ी होती हैं? बहरहाल, मस्क के इस कदम के बाद अमेरिकी राजनीति में हलचल मच गई है। यह उस दो-दलीय व्यवस्था के खिलाफ सीधी चुनौती है। मस्क ने इन दोनों पार्टियों को 'भ्रष्ट' बताकर तीसरे विकल्प की मांग को हवा दी है, जो युवाओं, उद्यमियों और तकनीक-प्रेमी वर्ग को आकर्षित कर सकता है। इसका आर्थिक प्रभाव भी गहरा हो सकता है। मस्क की छवि एक वैश्विक निवेशक और तकनीकी नवाचार के प्रतीक के रूप में है। अगर वह सत्ता की ओर बढ़ते हैं, तो निवेशक समुदाय और टेक सेक्टर में अस्थिरता या उम्मीद का माहौल बन सकता है। सामाजिक रूप से यह ध्रुवीकरण बढ़ा सकता है, क्योंकि ट्रंप समर्थक पहले ही मस्क को 'धोखेबाज' बता चुके हैं। वामपंथी खेमे में मस्क की लोकप्रियता पहले ही संदिग्ध रही है। इन तमाम परिस्थितियों में अभी यह ठीक-ठीक बता पाना जल्दबाजी होगी कि नई पार्टी का भविष्य क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका की राजनीति में एक नया अध्याय खुल चुका है।

देव प्रकाश बमनावत, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
अमेरिका पार्टी

मस्क का सियासी सफर आसान नहीं

अमेरिका में एलन मस्क ने अपनी पार्टी का एलान करके दोनों प्रमुख पार्टियों- रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक को चुनौती दी है। मस्क ने यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मनमुटाव के बाद उठाया है। एलन मस्क का कहना है कि वह इस पार्टी की फंडिंग खुद करेंगे। उनका दावा है कि यह पार्टी भ्रष्ट और दिखाविया 'यूनिपार्टी' को चुनौती देगी, जिसमें (एकदलीय व्यवस्था की तरह काम करने वाले दल) डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों शामिल हैं।

मस्क पहले ट्रंप के साथ थे, लेकिन अब वह रिपब्लिकन पार्टी के मौजूदा नेताओं को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। हालांकि, कहा यही जा रहा है कि मस्क की इस पार्टी के सफल होने की संभावना बहुत कम है। ट्रंप ने भी मस्क के इस कदम की आलोचना की है। वैसे भी, अमेरिका का राजनीतिक तंत्र तीसरे दल के लिए नहीं बना है। हालांकि, मस्क का कहना है कि वह इस पार्टी के जरिये लोगों को उनकी आजादी वापस दिलाना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह घोषणा की। मस्क ने नए विकल्प की जरूरत को भी रेखांकित किया है। उन्होंने कांग्रेस (अमेरिकी संसद) पर भी निशाना साधा है। मस्क ने कहा है कि कांग्रेस एक भ्रष्ट 'डेमोक्रेट-रिपब्लिकन यूनिपार्टी' का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने यह भी कहा कि देश को एक विकल्प की जरूरत है, ताकि लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिल सके।

बहरहाल, कई राजनीतिक विश्लेषक यही मानते हैं कि एलन मस्क का कदम सिर्फ दिखावा है। उनके मुताबिक, मस्क नीतिगत मसलों पर तब तक नहीं बोलते, जब तक कि इससे उनके व्यापार को खतरा नहीं होता। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि मस्क की 'अमेरिका पार्टी' के सफल होने की संभावना कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की राजनीति विज्ञानी जेना बेडनार का कहना है कि अमेरिका के चुनावी सिस्टम में तीसरे दलों के लिए कई बाधाएं हैं। बेडनार ने यह भी कहा कि मस्क अपनी संपत्ति का इस्तेमाल प्राइमरी चुनावों में मौजूदा नेताओं को चुनौती देने के लिए कर सकते हैं। इससे रिपब्लिकन पार्टी में बदलाव आ सकता है। हालांकि, उनका यह भी कहना है कि मस्क का ध्यान जल्द ही हट सकता है, क्योंकि प्राइमरी चुनाव 2026 तक नहीं होंगे। इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया में एक नई पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक समूह को 75,000 मतदाताओं को पंजीकृत करना होगा या 10 लाख से अधिक याचिका हस्ताक्षर के साथ एकत्र करने होंगे। यह भी कोई छोटी नहीं, बल्कि एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है।

परमानंद राय, टिप्पणीकार